राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण मंगलवार 20 जनवरी 2026 वर्ष-8,अंक-324 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बीवी- जी राम जी के बारे में झूठ फैलाकर कांग्रेस मजबूत नहीं कमजोर हो रही

-केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को घेरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर वीबी-जी राम जी के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि नया अधिनियम काम के अधिकार को मजबूत करेगा। उन्होंने मनरेगा की जगह लेने वाले नए अधिनियम के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष यह ''झूठ फैला रहा है कि इस योजना से रोजगार केवल कुछ पंचायतों में ही प्रदान किया जाएगा।

बता दें कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को निरस्त करने के विरोध में 45 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 'मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की है। विपक्षी दल विकसित भारत-रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग कर रहा है। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि मैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से कहना चाहता हूं कि वीबी-जी राम जी के बारे में गलत जानकारी फैलाकर वे कांग्रेस को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचार, विचारधारा और आदर्श को त्याग दिया है...विचार है राष्ट्र सर्वोपरि, देश का विकास...वीबी-जी राम जी गांवों के विकास के लिए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने मनरेगा को बेहतर बनाने की कोशिश की। इसका सबूत यह है कि हमने करीब नौ लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि यूपीए सरकार ने करीब दो लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि यह कहना 'झूठ है कि काम के अधिकार को छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम 100 दिन काम के बजाए, अब 125 दिन काम दे रहे हैं...सिर्फ काम करने का अधिकार ही नहीं, हमने 15 दिनों के अंदर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया है...आपने कागज पर अधिकार दिया, हमने जमीनी स्तर पर इसे और मज़बूत किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि वे यह गलत सूचना फैला रहे हैं कि रोजगार सिर्फ कुछ पंचायतों में ही दिया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह योजना सभी पंचायतों में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। केंद्र पहले से ही ज्यादा धनराशि दे रहा है। राज्य जो निवेश करेंगे, वह गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए होगा। मंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना छह महीने में लागू कर दी जाएगी और तब तक मनरेगा जारी रहेगा।

21 को कुरुक्षेत्र जाएंगे राहुल गांधी, जिला इकाई अध्यक्षों को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 जनवरी को कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के पार्टी के जिला इकाई अध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को हरियाणा के जिला इकाई अध्यक्षों को संबोधित करने के बाद यहां पत्रकारों को बताया कि गांधी 21 जनवरी को यहां पहुंचेंगे। कांग्रेस ने हरियाणा और उत्तराखंड में अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में इन राज्यों के जिला इकाई अध्यक्षों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। कुरुक्षेत्र में 13 से 22 जनवरी तक आयोजित इस शिविर में हरियाणा के 33 और उत्तराखंड के 27 जिला अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय बढ़ने के बजाय उनकी लागत कई गुना बढ़ गई है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप भी लगाया। हुड्डा ने दावा किया कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अब यह लाभ केवल सीमित संख्या में महिलाओं को ही मिल रहा है। मनरेगा की जगह लेने वाले नए अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी नीत सरकार ने दलितों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, ग्रामीणों और पंचायतों के अधिकारों पर हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में आठ लाख से ज्यादा मनरेगा कामगार होने के बावजूद, 2024-25 के दौरान केवल 2,100 परिवारों को ही 100 दिन का काम उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर केमिकल टैंकर और ट्रेलर की भिड़ंत, कोई हताहत नहीं

जयपुर (एजेंसी)। पावटा कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर रविवार रात करीब 8:40 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। जयपुर से दिल्ली जा रहे केमिकल टैंकर और दूसरी लेन से आ रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टैंकर में तुरंत आग लग गई। गनीमत रही कि टैंकर चालक समय रहते वाहन से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता था। सूचना मिलते ही प्रागपुरा थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से जयपुर-दिल्ली मार्ग को बंद कर ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर दिया। केमिकल से भरे टैंकर के कारण आग बुझाना चुनौतीपूर्ण था। दमकलकर्मी फोम और पानी का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को घेराबंदी कर राहगीरों को सुरक्षित रखा। प्राथमिकता अग्निकांड पूरी तरह नियंत्रित करना और हाईवे से वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करना है। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में 7 गिरफ्तार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 (पोक्सो) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस और परिवार के सूत्रों के अनुसार, किशोरी पुरुलिया शहर की रहने वाली है। शुक्रवार शाम 17 साल की लड़की एक दोस्त के घर जाने के लिए अपने घर से निकली। जब रात होने के बाद भी वह घर नहीं लौटी, तो परिवार को उसकी चिंता होने लगी। आखिरकार, लड़की के पिता ने पुरुलिया सदर पुलिस स्टेशन में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। लड़की को उसी रात बाद में बचा लिया गया। पूछताछ के दौरान, नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और कहा कि उसे अगवा किया गया था और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। लड़की ने पुलिस को बताया कि रात में सात-आठ लड़के उसे सड़क से उठाकर रेलवे ट्रैक के पास एक खेत में ले गए और, वहां उसके साथ गैंगरेप हुआ। इस घटना के बाद, लड़की किसी तरह घर वापस आ गई। तभी पुलिस को उसके बारे में पता चला। घटना सामने आने के तुरंत बाद लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने कई जगहों पर तलाशी ली। रविवार को पुलिस ने कथित तौर पर शामिल सात लड़कों को गिरफ्तार किया। उनमें से एक बीमार पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी छह को कोर्ट में पेश किया गया।

कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस रविंदर दुदेजा ने कहा कि सेंगर ने 10 साल की कुल सजा में से लगभग 7.5 साल हिरासत में बिताए हैं और इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला करने में देरी हुई है, लेकिन यह देरी आंशिक रूप से सेंगर द्वारा दायर की गई कई याचिकाओं के कारण हुई है। इसलिए, कोर्ट जमानत और सजा के निलंबन की याचिका खारिज कर दी। बता दें, उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता को सेंगर के इशारे पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस की बर्बरता के कारण हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने सेंगर और अन्य को उनकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई।

पाकिस्तानी प्लेन जैसा गुब्बारा मिला

किश्तवाड़ (एजेंसी)। जम्मू के खौर सेक्टर के पुलिस पोस्ट पल्लनवाला के अंतर्गत गांव कचरियाल में एक खुले मैदान से सोमवार को पाकिस्तानी प्लेन के आकार का गुब्बारा मिला। सफेद और हरे रंग के गुब्बारे पर पीआईए यानी पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले गुब्बारे को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद गुब्बारे को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस पोस्ट पल्लनवाला को सौंप दिया गया है। वहीं, किश्तवाड़ में लगातार दूसरे दिन आतंकियों की तलाश जारी है। इसे ऑपरेशन त्राशी-1 नाम दिया गया है। सेना ने घने जंग और खड़ी ढलानों वाले मुश्किल इलाके के कारण रविवार देर रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। सर्दी के मौसम के चलते यहां विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच रविवार को चतरू बेल्ट में मंडराल-सिंहपोरा के पास सोनार गांव में मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसमें 8 जवान घायल हो गए थे। आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके छर्रे जवानों को लगे हैं।

महिला पुलिसकर्मियों के टॉयलेट में कैमरा छिपाया

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में एक स्पेशल सब-इंस्पेक्टर ने महिला पुलिस अफसरों के टॉयलेट में हिडन कैमरा छिपा दिया। घटना का पता तब चला जब महिला पुलिसकर्मियों ने टॉयलेट में एक मोबाइल फोन देखा। जांच में पता चला कि मोबाइल आरोपी एसएसएआई का था। वह टॉयलेट के अंदर महिला पुलिसकर्मियों का वीडियो बना रहा था। हैरानी की बात यह है आरोपी ने रामनाथपुरम जिले के परमकुडी में घटना को उस समय अंजाम दिया जब वहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन स्वतंत्रता सेनानी त्यागी इमैनुएल सेकरन के मणि मंडपम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में राज्य के अलग-अलग इलाकों से महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। आरोपी एसएसआई परमकुडी नगर पुलिस थाने में तैनात था और मणि नगर चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहा था।

लद्दाख में भूकंप के तेज झटके

चेन्नई (एजेंसी)। लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और आसपास के इलाकों में सोमवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। लद्दाख के अलावा भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र लेह-लद्दाख क्षेत्र में जमीन से 171 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। भूकंप का केंद्र गहराई में होने के चलते कंपन विनाशकारी नहीं रहा। फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है।

पीएम मोदी ने एनडीआरएफ के जवानों की सराहना करते हुए कहा- ये संकट में उम्मीद की किरण

नई दिल्ली (एजेंसी)। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) आज अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल के जवानों की अदम्य बहादुरी, पेशेवर दक्षता और सेवा के प्रति उनके समर्पण की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री ने एक भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि एनडीआरएफ के जवान संकट के समय हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर न केवल लोगों की जान बचाते हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राहत प्रदान कर उम्मीद की किरण भी जगाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एनडीआरएफ के सभी पुरुष और महिला कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका पक्का इरादा और प्रोफेशनलिज्म मुश्किल समय में देश के लिए सबसे बड़ा संबल साबित होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब भी कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आती है, यह बल बिना थके सबसे चुनौतीपूर्ण हालातों में भी राहत और बचाव कार्यों में जुट जाता है। प्रधानमंत्री के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन और तैयारी के मामले में न केवल देश के भीतर एक मिसाल बनकर उभरा है, बल्कि इसने अपनी कार्यकुशलता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सम्मान अर्जित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्थापना दिवस पर बल के कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनडीआरएफ आज आपदा-प्रतिरोधी भारत बनाने के संकल्प में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज संकट के समय पूरा देश इस बल पर भरोसा करता है। उन्होंने उन शहीदों को भी नमन किया जिन्होंने दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जवानों के साहस और अटूट लगन को सलाम किया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई और जान बचाने के कौशल ने इस बल को लचीलेपन और तैयारी का प्रतीक बना दिया है। आज यह बल अपनी निस्वार्थ सेवा के कारण देश और विदेश दोनों ही जगहों पर प्रशंसा का पात्र बना हुआ है। स्थापना दिवस के इन संदेशों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति और एनडीआरएफ के जवानों के निरंतर संघर्ष को रेखांकित किया है।

माघ मेले में अव्यवस्था के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी

-सपा प्रमुख अखिलेश ने शंकराचार्य को स्नान से रोकने और समर्थकों की पिटाई की निंदा की

प्रयागराज (एजेंसी)। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और उत्तर प्रदेश की होम सेक्रेटरी मोहिता गुप्ता के साथ पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस के बाद विवाद बढ़ गया। स्थिति हाथापाई में बदल गई, जिससे मेले में अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या स्नान करने से इनकार कर दिया और अपनी पालकी के साथ बीच रास्ते से ही अखाड़े लौट गए। इस घटना के बाद से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने शंकराचार्य को स्नान से रोकने और समर्थकों की पिटाई की निंदा की।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने प्रयागराज में माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस द्वारा संगम में स्नान करने से रोकने और उनके कुछ समर्थकों की पिटाई की घटना की निंदा करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। यादव ने कि प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु-संतों-भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि यह घोर निन्दनीय है। सदियों से चली आ रही शाही-स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था।

सपा प्रमुख ने कहा कि सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में ही क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या का शाही-स्नान क्या पहली बार हो रहा है। इस अवस्था के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। उन्होंने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष की आलोचना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अहंकारी बीजेपी शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी 'एआई' पर मढ़ेंगे?

सीएम योगी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष मणिकर्णिका घाट पर हो रहे मरम्मत कार्य को गलत तरीके से पेश करने के लिए एआई से बनाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। सपा प्रमुख ने पूरे मामले की जांच की मांग की और कहा कि बीजेपी सरकार लापरवाह और संवेदनहीन है। बता दें रविवार को ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थकों को संगम में जाने से रोकने और विरोध करने पर कुछ समर्थकों की पिटाई किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है।

वहीं, शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को प्रशासन ने जानबूझकर स्नान करने से रोका और यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी। योगीराज ने दावा किया कि शंकराचार्य के समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से संगम नोज की तरफ स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन षड्यंत्र के तहत प्रशासन के लोगों ने समर्थकों को धक्का दिया और संतों को बर्बरतापूर्वक पीटा जो गलत है।

कांग्रेस असम में विधानसभा चुनावों में एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन नहीं करेगी: गोगोई

-पार्टी सत्ता में आई तो हिमंत सरमा की सभी अवैध संपत्तियों को करेंगे जब्त

डिब्रूगढ़ (एजेंसी)। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गोगोई ने हाजो-सुआलकुची निर्वाचन क्षेत्र के कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ की पूर्ण विफलता के बाद 2026 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी बाधा को पार करने की उसकी सोच पूरी तरह गलत है।

बता दें कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किए गए गठबंधन की तर्ज पर कई अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन बनाने पर काम कर रही है और इससे बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले एआईयूडीएफ को बाहर रखा गया है। उन्होंने 'बोर (ग्रेटर) असम' के निर्माण के लिए जनता से समर्थन की अपील की और सीएम हिमंत विसवा सरमा को राज्य का 'सबसे बेईमान' मुख्यमंत्री बताया है।

गोगोई ने दावा किया कि राज्य के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने जैसे वादे पूरे न करना यह साबित करता है कि सीएम सरमा एक बेईमान' मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमंत सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर अपार संपत्ति जमा कर रखी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर हिमंत सरमा सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर धर्म, भाषा, जातीयता और समुदाय के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाया।

गोगोई ने जोर देकर कहा कि ऐसी विभाजनकारी राजनीति केवल व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करती है, विकास की नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'शांति एवं सद्भाव का पुनर्निर्माण करेगी और गरीबों की सेवा उसी तरह करेगी जैसे पूर्व सीएम तरुण गोगोई ने की थी। राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी उन वादों को पूरा करने में 'विफल' रही, जिनके आधार पर वह सत्ता में आई थी।

पलायन की 36वीं बरसी पर कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतरे, हाईवे किया जाम

-घाटी में विस्थापित पंडितों के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के गठन की मांग

जम्मू (एजेंसी)। कश्मीरी पंडित पलायन की 36वीं बरसी के मौके पर जम्मू शहर के बाहरी इलाके जगती में देर रात हजारों कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर आए। पनुन कश्मीर के यूथ विंग के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया, जिसके चलते जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। उनका कहना था कि बीते तीन दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारों को लेकर कोई समाधान नहीं किया गया है।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का गठन शामिल है। उनका तर्क था कि बिना अलग प्रशासनिक व्यवस्था के सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी संभव नहीं है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने संसद में एंटी-जेनोसाइड बिल लाने की भी मांग की। कश्मीरी पंडितों ने सरकार से आग्रह किया कि उन्हें आधिकारिक तौर पर जनसंहार के पीड़ित के रूप में मान्यता दी जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने से देर रात तक यातायात बाधित रहा, जिससे सैकड़ों वाहन फंसे रहे और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालात को संभालने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सिविल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़े रहे कि उपराज्यपाल खुद मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुनें। इसी दौरान एक प्रदर्शनकारी हाईवे पर बने एक कलवर्ट से गिरकर घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। काफी देर बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की मांगों को लेकर असंतोष अब भी बरकरार है।

भारत आ रहे रूसी तेल टैंकर अचानक चीन की तरफ मुड़े, क्या अमेरिकी प्रतिबंधों का असर?

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस-यूक्रेन के मध्य जारी जंग के बीच पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर अब वैश्विक तेल व्यापार में साफ नजर आने लगा है। भारत और तुर्की की ओर जा रहे कई रूसी तेल टैंकर अब अपना रुख चीन की तरफ मोड़ते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि यह बदलाव अमेरिका और यूरोपीय संघ के सख्त प्रतिबंधों के डर और बढ़ती अनिश्चितता का नतीजा हो सकता है।

जानकारी के अनुसार हाल ही में पश्चिमी तुर्की के इजमित बंदरगाह पर पनामा के झंडे वाले टैंकर बेला-6 ने करीब एक लाख टन रूसी कच्चा तेल उतारा। यह डिलीवरी तुर्की की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी तुप्रास के लिए अपवाद मानी जा रही है, क्योंकि उसने यूरोपीय संघ के 21 जनवरी से लागू नए प्रतिबंधों से पहले रूसी तेल आयात में करीब 69 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। नए ईयू नियमों के तहत रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों का यूरोप में आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे भारत और तुर्की जैसी रिफाइनरियों पर सीधा असर पड़ा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिबंधों, ईरान और वेनेजुएला को लेकर अनिश्चितता तथा यूरोपीय संघ के नए फैसलों ने अंतरराष्ट्रीय तेल आपूर्ति को अस्थिर बना दिया है। लंदन स्थित जनरल इंडेक्स के विश्लेषक डेविड एडवर्ड का कहना है कि मौजूदा दौर असाधारण है, जहां भू-राजनीतिक उथल-पुथल सीधे ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रही है।

इस बीच भारतीय रिफाइनरियों ने भी सतर्क रुख अपनाया है। केप्लर के विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, भारत की प्रमुख रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल की खरीद कम कर 'स्वैच्छिक पाबंदी' लगा दी है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात 29 प्रतिशत घटकर तीन साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। इसके पीछे रूस की दिग्गज कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं।

भारत और तुर्की द्वारा छोड़े जा रहे इस अतिरिक्त रूसी तेल का एक हिस्सा चीन की ओर जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर में रूस से चीन के समुद्री मार्ग से तेल आयात में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कई ऐसे टैंकर, जिन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया, चीनी बंदरगाहों के पास देखे गए। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की छोटी स्वतंत्र रिफाइनरियां, जिन्हें 'टी-पॉट्स' कहा जाता है, सस्ते तेल की खरीद में माहिर हैं और जोखिम उठाने को तैयार रहती हैं। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि चीन

सभी छोड़े गए रूसी तेल को नहीं खपा पाएगा। फिर भी, बढ़ती छूट और सीमित जोखिम के चलते वह बड़ा खरीदार बना रह सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच के विरुद्ध बन रहे नए समीकरण

अमेरिका द्वारा हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य देशों (भारत, रूस, चीन एवं ब्राजील) पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की धमकी देना केवल अमेरिका की व्यापार नीति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की सीधी कोशिश है। 500 प्रतिशत का यह टैरिफ रूस, चीन, ब्राजील और भारत पर नहीं बल्कि ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा डीडोलराईजेशन की ओर अपने कदम बढ़ाने को रोकने का एक प्रयास है। ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में किए जाने वाले विदेश व्यापार का एक दूसरे को भुगतान अब स्थानीय मुद्रा में करते दिखाई दे रहे हैं।

(लेखक-प्रहलाद सबनानी)

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति श्री निकोलस मदुरो को रात्रि के समय में गिरफ्तार कर अमेरिका लाकर उन पर मुकदमा चलाया जाना एवं वेनेजुएला के तेल भंडार पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का कब्जा स्थापित करने का प्रयास करना, अमेरिका की साम्राज्यवादी सोच को ही दर्शाता है। साथ ही, इसी क्रम में डेनमार्क द्वारा शासित ग्रीनलैंड द्वीप पर भी अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। सोचनीय विषय है कि डेनमार्क नाटो का सदस्य देश होने के चलते वह अमेरिका का मित्र राष्ट्र है और मित्र राष्ट्र की सीमाओं में घुसकर उसके आधिपत्य वाले क्षेत्र को अमेरिका द्वारा बलपूर्वक अपने देश की सीमा में शामिल करने का प्रयास करना उचित कदम नहीं कहा जा सकता है। कुछ समय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कनाडा के राष्ट्रपति को धमकी दी थी कि अमेरिका कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। ध्यान रहे कनाडा भी अमेरिका के मित्र राष्ट्र के देशों की सूची में शामिल है। परंतु, जब अमेरिका जैसा देश साम्राज्यवादी सोच के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं, तो मित्र राष्ट्र का ध्यान भी नहीं रह पाता है।

अमेरिका द्वारा हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य देशों (भारत, रूस, चीन एवं ब्राजील) पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की धमकी देना केवल अमेरिका की व्यापार नीति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की सीधी कोशिश है। 500 प्रतिशत का यह टैरिफ रूस, चीन, ब्राजील और भारत पर नहीं बल्कि ब्रिक्स के सदस्य देशों द्वारा डीडोलराईजेशन की ओर अपने कदम बढ़ाने को रोकने का एक प्रयास है। ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में किए जाने वाले विदेश व्यापार का एक दूसरे को भुगतान अब स्थानीय मुद्रा में करते दिखाई दे रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा हैं। ब्रिक्स की मुद्रा व्यवस्था, स्थानीय मुद्रा व्यापार सम्बंध एवं डॉलर मुक्त भुगतान व्यवस्था अमेरिका के लिए एक रणनीतिक खतरे के रूप में उभर रही है। इसीलिए अमेरिका छोटे देशों की तरह ही बड़े देशों को भी अनुशासित करना चाहता है। परंतु, यहां अमेरिका यह भूल जाता है कि वेनेजुएला, डेनमार्क, क्यूबा, मेक्सिको आदि छोटे देश हैं जो अपनी जरूरतों के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं परंतु भारत, चीन, रूस एवं ब्राजील जैसे बड़े देशों पर अमेरिका का दबाव काम नहीं कर पाएगा। ट्रम्प प्रशासन की वर्तमान विदेश नीति को 20वीं सदी की 'हस्तक्षेपवाद.2' की नीति कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले 250 वर्षों में अमेरिका ने विश्व के अन्य देशों में 400 बार हस्तक्षेप किया है। अमेरिका के लिए यह एक पैटर्न है आश्चर्य में डालने वाली घटना नहीं है। अमेरिका ने पूर्व में भी आर्थिक दबाव डालकर एवं सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से अन्य देशों में सत्ता परिवर्तन कराने में भी सफलता हासिल की है। और, यह पैटर्न आज भी जारी है। अमेरिका भारत एवं चीन पर केवल इस कारण से भी 500 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहता है क्योंकि ये देश रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं। आज के इस युग में अब अमेरिका निर्णय लेगा कि किस देश को कच्चा तेल किस देश से खरीदना है। यह साम्राज्यवाद अथवा अधिनायकवाद की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है?

इसी प्रकार, ट्रम्प प्रशासन द्वारा विश्व के 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अमेरिका की सदस्यता को समाप्त करना भी वैश्विक व्यवस्था का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि अमेरिका का विश्व में एक छत्र राज्य स्थापित करने की सोच का नतीजा हो सकता है। अमेरिका किसी भी अन्य ब्लाक अथवा देश के साथ मिलकर विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करना चाहता है बल्कि अमेरिका केवल अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इस रणनीति के अंतर्गत वैश्विक संगठनों एवं संस्थाओं को कमजोर करने के एकपक्षीय अमेरिकी शक्ति मॉडल को लागू करना ही मुख्य लक्ष्य हो सकता है।

आज अमरीका में ट्रम्प प्रशासन इससे भी परेशान है कि आर्थिक शक्ति का केंद्र पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों की ओर खिसकता जा रहा है। इससे ट्रम्प को पूरे विश्व में अमेरिका का आधिपत्य स्थापित करने की रणनीति को धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है। संख्या, जनसंख्या, संसाधन एवं बाजार के आधार पर आगे आने वाला भविष्य पूर्व के आस पास दिखाई देता है, अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपने प्रभुत्व को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। अमेरिका आज नहीं चाहता कि चीन, रूस एवं भारत मिलकर विश्व में शक्ति की एक धुरी बनें। साथ ही, ट्रम्प यह भी नहीं चाहता कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी रणनीतिक स्वायतत्ता बढ़ाने में सफल हो तथा डीडोलराईजेशन की व्यवस्था गति पकड़े और यूरोपीय यूनियन के देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए। यूरोपीय यूनियन के देशों पर अमेरिका अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। परंतु, अब तो यूरोपीय यूनियन के देश भी अपने सुरक्षा बजट में अतुलनीय वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका पर इन देशों का विश्वास कम हो गया है। ट्रम्प चूंकि बहुध्रुवीय व्यवस्था में विश्वास नहीं करते है और यह व्यवस्था उनके लिए असहनीय है अत: ट्रम्प समस्त देशों पर टैरिफ युद्ध छेड़कर उन्हें दबाव में लाना चाहते है ताकि अमेरिका पूरे विश्व में अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर सके। इसीलिए ट्रम्प आज पूरे विश्व में नियंत्रित अशांति चाहता है। दरअसल, आज अमेरिका की आक्रामक साम्राज्यवादी टैरिफ नीति भी वैश्विक अस्थिरता की सबसे बड़ी जड़ के रूप में उभर रही है।

इसी क्रम में, अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्यवाही कर ग्रीनलैंड पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कार्यवाही नाटो जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान को तोड़ सकती है। नाटो के सदस्य देशों ने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड पर हमला नाटो के सदस्य देशों पर किया गया हमला माना जाएगा। इससे यूरोपीयन देशों एवं अमेरिका के बीच दुर्लभ एवं खतरनाक तनाव दिखाई दे रहा है।

वैश्विक स्तर पर वर्तमान में उभर रही परिस्थितियों को सर्वांगी कूटनीतिक युद्ध की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस सर्वांगी कूटनीतिक युद्ध में कच्चे तेल की उपलब्धता पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, डॉलर पर अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखने के प्रयास ताकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका का मुद्रा पर नियंत्रण लगातार आगे भी बना रहे, समुद्री मार्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, तकनीकी सम्पदा को अपने कब्जे में रखना, वैश्विक सप्लाई चैन को प्रभावित करना एवं आरटीफिशीयल इंटेलिजेन्स आदि के माध्यम से ट्रम्प अन्य देशों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज प्रत्यक्ष युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संरचना को पुनर्गठित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस रचना में ट्रम्प अपने आप को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में अमेरिका चाहता है कि दुनिया फिर से उसी मोड में लौट आए, जहां वित्त, व्यापार, सैन्य गठबंधन और तकनीक सब उसकी चौखट पर खड़े हों। आज अमेरिका का लक्ष्य सम्भवत- तीसरा विश्व युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक व्यवस्था को अमेरिका के प्रभुत्व में पुनर्गठित करना है।

अमेरिका का 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अपने आप को अलग करने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस से बाहर निकलना पूरे विश्व को स्पष्ट संदेश देता है कि अमेरिका की अब पर्यावरण के क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार कार्यक्रमों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है तथा वह इस अलायंस को दी जाने वाली अमेरिकी मदद को रोकना चाहता है और वैश्विक स्तर पर केवल अपने प्रभाव को बढ़ाने में ही अपनी पूरी शक्ति लगाना चाहता है। विश्व के भले की बात भी अब अमेरिका को नागवार गुजर रही है। जबकि आज जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट को कम करने अथवा दूर करने में समस्त देशों का आपसी सहयोग अति आवश्यक है। भारत एवं फ्रान्स के संयुक्त नेतृत्व में बनाया गया यह मंच विकासशील देशों के लिए उम्मीद की किरण बन रहा है।

विश्व के अन्य देशों में यह भावना विकसित हो रही है कि आज वैश्विक स्तर पर एक ऐसी दुनिया विकसित होती दिखाई दे रही है जिसमें अमेरिका अकेला खड़ा हो एवं विश्व के अन्य समस्त देश आपस में तालमेल रखते हुए अपने विकास को गति दें।

वैसे भी, विश्व पहिले से ही इस मुहाने पर आकार खड़ा है जहां अकेले चलना बहुत मुश्किल है हर पग पर विभिन्न देशों को अन्य देशों के सहायता की अति आवश्यकता है। एक दूसरे के सहयोग के बिना सम्भवत- कोई भी देश आज आर्थिक विकास के पथ पर अपनी दौड़ को गति प्रदान नहीं कर पाएगा।

इसीलिए वैश्विक स्तर पर आज नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका को छोड़कर ये देश आपस में मुक्त व्यापार समझौते तेजी से सम्पन्न कर रहे हैं ताकि ये, अपने देश के आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकें।

संपादकीय

रोजगार सृजन से संभव विकसित भारत का संकल्प

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, जिसमें गत दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8 फीसदी होने की बात कही गई है। भारत दुनिया में युवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम इस युवा शक्ति का भरपूर उपयोग राष्ट्र विकास में नहीं कर पा रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि देश के शहरी क्षेत्र में पंद्रह वर्ष से अधिक आयुवर्ग के युवाओं में बेरोजगारी की दर गांवों के मुकाबले ज्यादा है। जहां शहरों में यह प्रतिशत बढ़कर 6.7 फीसदी हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में यह 3.9 फीसदी स्थिर है। हाल ही के वर्षों में बेरोजगारी देश में बड़ा मुद्दा रहा है, जो भारत जैसे विकासशील देश के हित में नहीं है। किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास दर तभी सार्थक होगी, जब रोजगार के नये मौके उपलब्ध हो रहे हों। नीति-नियंताओं को आत्ममंथन करना होगा कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रोजगार के नये अवसर क्यों नहीं बन रहे हैं। सरकारें सुनिश्चित करें कि युवाओं को देश की तरक्की में योगदान देने का अवसर मिले। यदि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है तो इसके मायने हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में नौकरी के मौके बढ़ नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में एआई और डिजिटलीकरण के चलते भी नौकरियां घटी हैं। तो क्या हम इस चुनौती के लिये अपने युवाओं को तैयार कर रहे हैं? निश्चित रूप से देश के नीति-नियंताओं को मंथन करना चाहिए कि 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्किल इंडिया' जैसे अभियानों के जमीनी परिणाम उत्साहवर्धक क्यों नहीं हैं? युवाओं की कौशल विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के बावजूद रोजगार के मौके क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समय के साथ कदमताल नहीं कर पा रही है? विडंबना यह भी है कि बढ़ती आबादी के बावजूद सरकारी क्षेत्र की नौकरियां कम हो रही हैं। युवाओं की शिकायत होती है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में तमाम तरह की विसंगतियां व्याप्त हैं। वे परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाते रहे हैं। निस्संदेह, बढ़ती बेरोजगारी हमारे विकास के मापदंडों पर भी सवाल खड़ी करती है। निश्चित रूप से संतुलित आर्थिक विकास की सार्थकता के लिए जरूरी है कि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़े तथा आर्थिक असमानता भी दूर हो। तेज विकास दर के साथ लोगों के जीवन में खुशहाली भी आनी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ने से ही समाज में खुशहाली आ सकती है। जब देश में रोजगार के मौके बढ़ेंगे तो समाज में वास्तविक समृद्धि आ सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ने से उत्पादकता बढ़ेगी और महंगाई पर नियंत्रण पाने में भी मदद मिलेगी। निस्संदेह, बढ़ती क्रय शक्ति भी अर्थव्यवस्था को गति देती है। निर्विवाद रूप से बेरोजगारी कम किए बिना हम देश के सौ साल पूरे होने तक विकसित भारत का लक्ष्य मुश्किल से हासिल कर पाएंगे। हमें एआई व डिजिटल चुनौती के मुकाबले के लिए युवाओं का कौशल विकास तेज करना चाहिए।

मेडीकल शिक्षा से मज़ाक यानी, मरीजों की जान से खिलवाड़

(लेखक-डॉ योगेन्द्र श्रीवास्तव)

खबर है कि इस साल नीट पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट) में हजारों सीटें खाली रह जाने के कारण नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडीकल साइंसेज (हृक्चश्वस्र) ने कट ऑफ को घटाकर (माइनस)- 40 पर्सेंटाइल कर दिया है। यानी जीरो पर्सेंटाइल से भी 40 कम। इसे समझने के लिए नीट पीजी परीक्षा का मूल्यांकन समझना जरूरी है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा में कुल 800 अंक होते हैं जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन में माइनस मार्किंग भी की जाती है ताकि कोई सिर्फ अनुमान के आधार पर सवाल का जवाब चुन कर अंक हासिल करने की जुर्रत न करे। इसीलिए एक सही जवाब पर यदि 4 अंक दिए जाते हैं तो एक गलत जवाब पर 1 अंक काट लिया जाता है। एक रोचक परिस्थिति यह है कि कोई परीक्षार्थी एक भी प्रश्न का जवाब न दे तो भी उसे जीरो पर्सेंटाइल प्राप्त होना निश्चित है। दूसरे शब्दों में बिना कोई भी किताब पढ़े या बिना किसी तैयारी के कोई भी परीक्षार्थी जीरो पर्सेंटाइल हासिल कर सकता है। और कट ऑफ घटाने के नए फरमान के बाद तो कोई परीक्षार्थी सिर्फ दिल बहलाने के लिए परीक्षा दे, कंप्यूटर पर आंसर शीट में एक भी सही जवाब न दे सके और चालीस प्रश्नों के गलत जवाब दे तो भी पीजी करने की पात्रता रखता है।

इन मापदण्डों पर हमारा सिस्टम कैसे डॉक्टर तैयार करना चाहता है, यह सामान्य समझ से परे और गहरी चिन्ता का विषय है। खेदजनक तथ्य यह है कि आम जनता इस खतरनाक खेल से बिल्कुल बेखबर है। बेशुमार प्राइवेट मेडीकल कॉलेज खोलने के साथ साथ लगभग सभी राज्य सरकारें राजनीतिक शिगूफे के तौर पर हर छोटे बड़े शहर में सरकारी मेडीकल कॉलेज भी खोलते जा रही हैं। इन नए नए मेडीकल कॉलेजों में न ही वांछित इन्फ्रास्ट्रक्चर है और न ही डॉक्टर एवं स्टॉफ। मगर हर साल हजारों डॉक्टर बदस्तूर डिग्री लेकर निकल रहे हैं। अनुभवी शिक्षकों और सभी प्रकार के मरीजों के अभाव में ये छात्र अधकचरा ज्ञान प्राप्त करके भी मरीजों का उपचार करने के लिए अधिकृत हैं। इनकी गुणवत्ता संदिग्ध है और ये निश्चित तौर पर खतरे से अनभिज्ञ मरीजों की जान के लिए खतरा बनेंगे। अभी लोग भूले नहीं हैं कि इस सदी के शुरुआत में किस तरह हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और आखिर छात्रों के अभाव में बंद भी हो गए। गुणवत्ता का हाल यह था कि बमुश्किल 17- 18 फीसदी ग्रेजुएट किसी रोजगार के काबिल थे। मगर मेडीकल कॉलेज में शिक्षा का स्तर इस तरह गिराना सीधे मरीजों की जान से खेलने के समान है।

लेकिन फ़िक्र किसे है? स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बेलगाम महत्वाकांक्षा ने सरकारों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और जमीनी हकीकत से अनजान नेता और अफसर अंधाधुंध मेडीकल कॉलेज खोलने की अनुमति देते जा रहे हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप मेडीकल शिक्षा की नियामक संस्था राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने मेडिकल कॉलेज खोलने के पैरामीटर बहुत शिथिल कर दिए हैं लेकिन उसके बावजूद अधिकांश मेडीकल कॉलेज सारे पैरामीटर पूरे नहीं करते। मगर खुद एनएमसी की मेहरबानी है कि सबको लाइसेंस मिल जाता है और उसका नवीनीकरण भी हो जाता है।

इसी का नतीजा है कि अब देश में लगभग 800 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं जिनमें स्ग्रक्चस्र की लगभग सवा लाख और पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की लगभग 80 हजार सीटें उपलब्ध हैं। लगभग सभी प्राइवेट मेडीकल कॉलेज राजनेताओं और रसूखदार धनाढ्यों द्वारा पोषित और संचालित हैं इसलिए सिस्टम ने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर रखी हैं। अब अगर सीटें खाली रहती हैं तो उतने छात्रों की फीस का घाटा है और जाहिर है कि मेडीकल कॉलेज खोलने और चालू रखने में भारी लागत के चलते कोई भी मालिक घाटा सहने को तैयार नहीं है। सो लाजिमी है कि सरकार पर दबाव होना ही था कि सीटें खाली न जाएं। बहरहाल कट ऑफ की पेशकश की गई और हृक्चश्वस्र द्वारा फौरन समस्या का समाधान कर दिया गया।

सरकारी पक्ष यह है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर पढ़कर निकलेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। मगर हक़ीक़त यह है कि नाकाबिल डॉक्टर्स की फौज स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाढार करेगी। असल समस्या ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की है जहां ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीधारी डॉक्टर जायेंगे ही नहीं। पीजी डिग्रीधारी ये सभी डॉक्टर प्राइवेट क्लीनिक या छोटे बड़े अस्पतालों में सेवाएं देंगे। वांछित योग्यता और उचित शिक्षा के अभाव में इनकी गुणवत्ता पर संदेह स्वाभाविक है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि करत करत अभ्यास के, जड़मति होय सुजान इसीलिए शायद सरकार ने योग्यता की जरूरत खत्म करने का निर्णय लिया हो। लेकिन संदेह यह है कि अधिकांश कॉलेजों के अधूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर में शिक्षकों के बिना अभ्यास करने वाले ये जड़मति कितना सीख पाएंगे?

आम नागरिक किसी नाम के पहले डॉक्टर की पदवी पढ़कर ही आश्वस्त हो जाता है कि उसे उचित इलाज मिलेगा। मगर वह इस तथ्य से अनजान ही रहेगा कि उक्त डॉक्टर को नीट पीजी में माइनस 40 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त हुए थे। हो सकता है भविष्य में डॉक्टर के साइन बोर्ड पर डिग्री के साथ नीट पीजी के अंक प्रदर्शित करने की मांग उठे ताकि मरीज उसकी काबिलियत का अनुमान लगा सकें। कई डॉक्टर अपनी योग्यता का डंका पीटने के लिए नाम और डिग्री के साथ गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह लिखते हैं। इसी तर्ज पर यह कानून बनाया जाना भी जरूरी है कि साइन बोर्ड पर नाम और डिग्री के साथ नीट पीजी के पर्सेंटाइल लिखना भी अनिवार्य हो।

राजनेता और आला अफसर अपना इलाज देश के सबसे महंगे अस्पतालों में सरकारी खर्च पर करवाते हैं। कुछ तो भारत की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं करते और विदेश जाकर इलाज कराते हैं। मगर आम लोगों के इलाज के लिए माइनस 40 पर्सेंटाइल वाले डॉक्टरों की जमात तैयार की जा रही है। सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की आड़ ले लेकिन यह मेडीकल शिक्षा के नाम पर सरासर मज़ाक हो रहा है। ऐसे नाकाबिल डॉक्टरों को इलाज की छूट देना दरअसल मरीजों की जान से खिलवाड़ है। ताजातरीन खबर यह है कि हृक्चश्वस्र के तुगलकी फरमान को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। लेकिन सरकार की इस मनमानी के खिलाफ आखिर आम जनता को ही आवाज उठाना होगी।

धर्मराज युधिष्ठिर ने निभाया था भ्रातृ धर्म

गहन वन से तृषार्त पाण्डव गुजर रहे थे। पानी की तलाश में वे इधर-उधर घूम ही रहे थे कि अकस्मात उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जल पीने के पूर्व ही मृत्यु का ग्रास बन गए। कारण यह था कि एक यक्ष ने उनसे प्रश्न किए थे, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही पानी पीने लगे। लेकिन वे यक्ष का कोपभाजन बने और उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई।

इतने में युधिष्ठिर आए और पानी पीने की कोशिश करने लगे। उनसे भी यक्ष ने प्रश्न किए, जिनके युधिष्ठिर ने समुचित उत्तर दे दिए। तब यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा, तुम जल पीने के अधिकारी हो। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे चारों भ्राताओं में से किसी एक को जीवन दान दूं। बोलो, मैं किसे पुनर्जीवित करूं?

प्रश्न बड़ा ही विचित्र था और साथ ही कठिन भी, क्योंकि युधिष्ठिर को चारों भाई एक समान प्रिय थे, तथापि एक क्षण भी सोचे बिना वे बोले, यक्षश्रेष्ठ आप नकुल को ही जीवन दान दें। यक्ष हंस पड़ा और बोला, धर्मराज, कौरवों से युद्ध में भीम की गदा और अर्जुन का गांडीव बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इन दो सगे भाइयों को छोड़कर नकुल का जीवन क्यों चाहते हो।

धर्मराज बोले, यक्षश्रेष्ठ हम पांचों भ्राता ही माताओं के स्नेह चिह्न हैं। माता पुंती के पुत्रों से मैं शेष हूं, किंतु माद्री मां के तो दोनों ही पुत्र मर चुके हैं। अत- यदि एक के ही जीवन का प्रश्न है, तो माद्री मां के नकुल का ही पुनर्जीवन इष्ट है। यक्ष ने सुना, तो भावविह्वल हो बोला, युधिष्ठिर तुम धर्मतत्व के ज्ञाता हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में धर्म के अवतार हो या नहीं। अतएव मैं चारों भाईयों को जीवन देता हूं।

विचार मंथन

भ्रष्टाचार पर चीन ने दिखाई सख्ती अब भारत की बारी

(लेखक-सनत जैन)

चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वर्ष 2025 में चीन ने लगभग 10 लाख लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया और उनमें से 9.83 लाख दोषी ठहराए गए। जो अब सजा भुगत रहे हैं। यह कार्यवाही सिर्फ संख्या दर्शानी वाली नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रमाण है जिसके दम पर चीन ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम करने में सफल हुआ है। 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार उन्मूलन का काम शुरू हुआ। इस अभियान में अब तक 72 लाख से अधिक मामलों की जांच हो चुकी है। बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सरकारी और निजी कंपनियां इत्यादि का कोई भी क्षेत्र कार्यवाही से अछूता नहीं रहा। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खास बात यह है, यहां 卐बड़ा आदमी卐 या 卐महत्वपूर्ण पद卐 पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचारियों का बचाव नहीं कर पाते हैं। 2025 में चीन के 69 शीर्ष अधिकारी ,केंद्रीय मंत्री स्तर से लेकर प्रांतीय प्रमुखों के पदों पर बैठे हुए लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होने के बाद सजा दी गई है। सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन और नेशनल कमीशन ऑफ सुपरविजन के जरिए पार्टी और सरकार ने यह संदेश दिया है, महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों को सत्ता को पिंजरे में रखना जरूरी है। टीवी डॉक्यूमेंट्री के जरिए भ्रष्टाचार के तरीकों और दोषियों के कबूलनामों को चीन में सार्वजनिक किया जा रहा है। इसके कारण भ्रष्टाचारियों में भारी भय व्याप्त है। आम जनता सजग हुई है। वह शिकायत करने के लिए अब सामने आ रही है। भारत में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। भ्रष्टाचारी यदि सत्ता पक्ष का है तो उसके बचाव करने के लिए पूरा शासन और प्रशासन तंत्र सामने आ जाता है। 2014 के बाद से सत्ता पर बैठे हुए लोग और प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भारत में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है जो कार्रवाई हो रही है वह छोटे-छोटे पदों में बैठे हुए लोगों के खिलाफ हो रही है। भारत में भ्रष्टाचार कॉरपोरेट तरीके से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भारत में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर दर्ज ही नहीं होते हैं, वर्षों तक जांच के नाम पर लटके रहते हैं। बड़े नेता और अफसर कानूनी जटिलताओं, राजनीतिक संरक्षण और 卐वाशिंग मशीन卐 जैसी प्रक्रियाओं से बचे रहते हैं। नतीजा यह कि भारत की आम जनता छोटे-छोटे से कामों के लिए भ्रष्टाचार की चक्की में पिस रही है। भारत में नौकरशाही के साथ-साथ अब न्यायपालिका के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायपालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको लेकर आम जनता में सिस्टम पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। भारतीय दंड संहिता में जो नए प्रावधान किए गए हैं, उसके अनुसार शासन की अनुमति के बिना भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई संभव ही नहीं है। भारत में एफआईआर दर्ज न होने से सरकार और उसके अधिकारी अपने आप को ईमानदार बताने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। आंकड़ों को बेहतर दिखाने और भ्रष्टाचार मुक्त बताने के लिए सरकार स्वयं भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का काम करती है। जिसके कारण भारत में भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है।

चीन का उदाहरण दिखाता है, भ्रष्टाचार से लड़ाई सिर्फ कानून बनाने से नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत और उसकी जांच बिना अपवाद, जांच करने एवं कठोर कार्यवाही करने से भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। चीन में सरकार भ्रष्टाचार के मामलों से घबराती नहीं है। वह बेहतर शासन देने के लिए भ्रष्टाचारियों पर बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्यवाही कर रही है। यह संदेश जनता को देती है। बिना किसी भेदभाव के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करने के कारण चीन में सरकार की इमेज आम जनता में बहुत अच्छी है। चीन में भ्रष्टाचार करने से प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग डरने लगे हैं। यह स्थिति भारत में एक बार 1975 से 1977 के बीच में जब आपातकाल लगा था तब देखी गई थी। उस समय शासन और प्रशासन के सभी तंत्र भ्रष्टाचार और कानून विरोधी काम करने से डर रहे थे। भारत में यदि भ्रष्टाचार सचमुच कम करना है तो शुरुआत राजनीतिक ईमानदारी से करनी होगी। खासकर चुनावी खर्च और सत्ता के संरक्षण में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है। जहां सरकार के मुखिया का संकल्प मजबूत होता है, वहां सिस्टम सुधरता है। इस बात का प्रमाण आपातकाल का दौर था। चीन ने यह करके दिखाया है। बिना किसी भेदभाव के सख्ती और निरंतर कार्रवाई करने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। पिछले 11 वर्षों में भारत में केवल विपक्षियों के ऊपर कारवाई हो रही है। सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए अधिकारियों और न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने से भारत में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चीन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, भारत के लिए वह एक सबक है। कानून सबके लिए बराबर हो, तभी लोकतंत्र और शासन तथा सामाजिक व्यवस्था मजबूत होगी। किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब सभी पक्ष ईमानदारी से अपना काम करें। चीन ने यह करके दिखा दिया है।

बजट में राजकोषीय अनुशासन और अर्थव्यवस्था स्थिर रखने पर रहेगा जोरः विशेषज्ञ

– सरकार कोई बड़े और चौंकाने वाले सुधारों की घोषणा नहीं करेगी

नई दिल्ली ।

भारतीय शेयर बाजार यह मानकर चल रहे हैं कि केंद्रीय बजट 2026 में सरकार कोई बड़े और चौंकाने वाले सुधारों की घोषणा नहीं करेगी। यह बजट रविवार, 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा। विश्लेषकों के मुताबिक सरकार का मुख्य जोर लोकलुभावन उपायों की बजाय राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने पर रहेगा। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्यक्ष करों से जुड़े अहम बदलाव पिछले बजट में किए जा चुके हैं, जबकि जीएसटी से जुड़े सुधार सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। ऐसे में बजट 2026 में बड़े टैक्स बदलावों की संभावना कम है। सरकार सीमित संसाधनों में संतुलित खर्च की नीति अपना सकती है। अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 27 में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के करीब 4.2 फीसदी तक सीमित रखने की कोशिश करेगी। टैक्स से सीमित आय वृद्धि को देखते हुए सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए संसाधन जुटा सकती है। रक्षा, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर में पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। बाजार` विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का फोकस आर्थिक स्थिरता और सुधारों पर रहेगा। पीएलआई स्कीम को आगे बढ़ाने, एमएसएमई और निर्यातकों को राहत देने तथा नियमों को सरल बनाने के कदम उठाए जा सकते हैं। एक अर्थशास्त्री का मानना है कि रक्षा खर्च में 12-15 फीसदी और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में 8-10 फीसदी तक बढ़ोतरी संभव है। बैंक आफ अमेरिका का कहना है कि सरकार वित्त वर्ष 27 से कर्ज प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान दे सकती है और कर्ज-से-जीडीपी अनुपात को 55 फीसदी तक लाने का लक्ष्य तय कर सकती है।

कुल मिलाकर, बजट 2026 को लेकर बाजार की उम्मीदें स्थिरता, अनुशासन और दीर्घकालिक विकास पर टिकी हुई हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा बना रह सकता है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ ही 90.87 पर बंद हुआ। वहीं रुपया सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन सुबह 12 पैसे की बढ़त के साथ 90.66 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा विश्लेषकों ने बताया कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के कमजोर रुख से घरेलू मुद्रा को बढ़ावा मिला। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और अस्थिर भू-राजनीतिक स्थिति के बीच विदेशों में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशक सतर्क रहे। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिका डॉलर के मुकाबले 90.68 पर खुला। फिर 90.66 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 12 पैसे की बढ़त दिखाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.78 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21 फीसदी की गिरावट के साथ 98.99 पर रहा।

23, 24, 25 और 26 जनवरी को बैंक रहेंगे बंद

मुंबई । देश के कुछ चुनिंदा शहरों में शुक्रवार, 23 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे। अगरतला, भुवनेश्वर और कोलकाता में इस दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। छुट्टी का कारण स्थानीय पर्व और विशेष अवसर हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सरस्वती पूजा, वीर सुरेंद्र साईं जयंती और बसंत पंचमी। इसके अलावा बाकी शहरों में बैंक सामान्य समय पर खुलेंगे। 24 जनवरी चौथा शनिवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। यह नियम हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार पर लागू होता है। रविवार, 25 जनवरी को साप्ताहिक अवकाश के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। सोमवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय छुट्टी के कारण पूरे देश में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी।

वेदांता की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील को 1,255 करोड़ का नोटिस

- कंपनी पर अपने खनन पट्टों में न्यूनतम उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य पूरे नहीं करने का आरोप

मुंबई । ओडिशा सरकार ने देश की दिग्गज माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड को लगभग 1,255 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ओडिशा के क्योंझर जिले के कोइरा सर्किल की खदानों से संबंधित है। सरकार का आरोप है कि कंपनी ने अपने खनन पट्टों में न्यूनतम उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य पूरे नहीं किए जो माइनरल कनसेशन रूल्स 2016 के तहत अनिवार्य हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के कार्यालय ने ईएसएल स्टील को दो अलग-अलग नोटिस भेजे हैं। नोटिस के अनुसार, कंपनी की बीको और फीग्रेड माइनिंग लीज पर खदान संचालन के चौथे वर्ष में तय उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य पूरे नहीं हुए। नियमों के तहत यदि कोई कंपनी न्यूनतम खनन सीमा से कम उत्पादन करती है, तो उसे सरकार को जुर्माना या निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। ईएसएल स्टील ने नोटिस पर आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि नोटिस में दी गई गणना और आधार कानूनी व तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वह नोटिस की विस्तृत समीक्षा कर रही है और अपने हितों की रक्षा के लिए सभी कानूनी विकल्प अपनाएगी। इसमें कोर्ट से स्टे और नोटिस रद्द कराने की प्रक्रिया शामिल है। कंपनी का दावा है कि कानूनी मोर्चे पर उसका पक्ष मजबूत है।

चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में 5 फीसदी वृद्धि के करीब

हांगकांग । चीन की अर्थव्यवस्था 2025 में मजबूत निर्यात के दम पर लगभग 5 फीसदी की वार्षिक दर से बढ़ी। यह सरकार के आधिकारिक लक्ष्य के अनुरूप है। हालांकि, साल की आखिरी तिमाही में वृद्धि धीमी होकर 4.5 फीसदी रह गई, जो 2022 के बाद से सबसे धीमी तिमाही वृद्धि मानी गई। पिछली तिमाही में यह 4.8 फीसदी थी। निर्यात ने कमजोर उपभोक्ता खर्च और व्यावसायिक निवेश की भरपाई की। चीन ने रिकॉर्ड 1200 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज किया। संपत्ति बाजार में मंदी और कोविड-19 के व्यवधानों के बाद सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास कर रही है।

भारत कोकिंग कोल के शेयर की शानदार शुरुआत, 96.5 प्रतिशत चढ़ा

नई दिल्ली । कोल इंडिया की इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) का शेयर सोमवार को बाजार में लिस्टेड हुआ। बीएसई पर यह 45.21 और एनएसई पर 45 रुपए पर खुला, जो कि निर्गम मूल्य 23 रुपए से क्रमशः 96.56 और 95.65 फीसदी अधिक है। लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार मूल्यांकन 19,456.95 करोड़ रुपए रहा। निवेशकों ने शेयर पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी, जिससे इसका शुरुआती मूल्य लगभग दोगुना हो गया। बीसीसीएल ने 1,071 करोड़ रुपए के आईपीओ में केवल कोल इंडिया के 46.57 करोड़ शेयर बेचे। इसमें नए शेयर जारी नहीं किए गए। निर्गम मूल्य रेंज 21-23 रुपए तय की गई थी।

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते में गैर-शुल्क बाधाओं पर जोर की सिफारिश

- यूरोपीय संघ के प्रमुख अधिकारी 25-27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे

नई दिल्ली ।

18 साल से चल रही भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता अब अंतिम चरण में है। यूरोपीय संघ के प्रमुख अधिकारी 25-27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे और 27 जनवरी को वार्ता के निष्कर्ष की घोषणा की संभावना है।

आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने कहा कि भारत को कृषि और दवा क्षेत्रों में गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने के लिए ईयू पर दबाव डालना चाहिए। केवल शुल्क कटौती से निर्यातकों को पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। गैर-शुल्क बाधाओं में दवा अनुमोदन में देरी, खाद्य और कृषि उत्पादों पर कड़े स्वच्छता और पादप/पशु स्वास्थ्य नियम, साथ ही जटिल परीक्षण और प्रमाणीकरण शामिल हैं। बासमती चावल, मसाले और चाय जैसे उत्पाद अक्सर कीटनाशक अवशेष मानकों के कारण अस्वीकार किए जाते हैं। समुद्री उत्पादों पर एंटीबायोटिक दवा की चिंता से अतिरिक्त नमूना परीक्षण होता है। विनिर्माण क्षेत्र में 'रीच' नियम और जलवायु विनियम छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लागत बढ़ाते हैं। 1 जनवरी से लागू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों पर लागू है। जीटीआरआई ने कहा कि भारत को अमेरिका के समान छूट या सुरक्षा प्रावधानों की मांग करनी चाहिए। ईयू भारत के लगभग 600 अरब डॉलर के सरकारी खरीद बाजार में प्रवेश चाहता है। भारत सीमित पहुंच प्रदान कर सकता है, जैसा कि उसने ब्रिटेन के साथ किया था।

भारतीय शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 324, निफ्टी 108 अंक नीचे आया

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरवट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी होने से बाजार नीचे आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 324.17 अंक टूटकर 83,246.18 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 108.85 अंक नीचे आकर 25,585.50 पर बंद हुआ। बाजार में आज रियल्टी, मीडिया और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के शेयर गिरे। निफ्टी रियल्टी 1.99 फीसदी, निफ्टी मीडिया 1.84 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.56 फीसदी, निफ्टी इन्फ्रा 0.90 फीसदी नीचे आया। वहीं निफ्टी एफएमसीजी 0.67 फीसदी, और निफ्टी ऑटो 0.13 फीसदी नीचे आया। सेंसेक्स पैक में टेक महिंद्रा, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, आईटीसी, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व सबसे अधिक लाभ वाले शेयर रहे जबकि आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, इन्फोसिस, भारती एयरटेल के शेयर गिरे। लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली हावी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 220.15 अंक फिसलकर 59,647.65 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 171.60 अंक नीचे आकर 17,190.70 पर बंद हुआ था।

जानकारों के अनुसार टैरिफ को लेकर चिंताएं फिर से हावी होने के कारण बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। इससे बाजार धारणा प्रभावित रही है। इससे पहले आज सुबह बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 498 अंक गिरकर 83,072 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 50 में 134 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 25,560 पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों को लेकर ग्रीनलैंड खरीद योजना के विरोध पर टैरिफ लगाने की चेतावनी से भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है, इससे घरेलू बाजार पर भी प्रभाव पड़ा है।

नए लेबर कोड से प्राइवेट सेक्टर में बढ़ा कर्मचारी खर्च

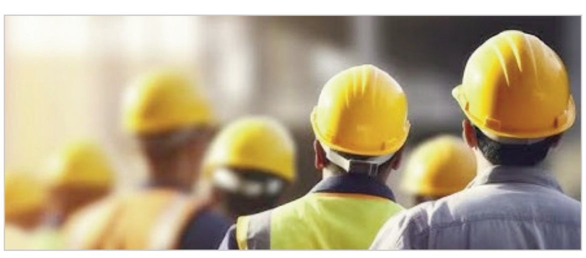

नई दिल्ली ।

नवंबर 2025 में लागू नए लेबर कोड का असर प्राइवेट सेक्टर पर दिखने लगा है। एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में 18,770 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग खर्च दर्ज किया, जो` वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के 17,110 करोड़ रुपए से अधिक है। बैंक ने बताया कि कर्मचारी लागत में 800 करोड़ रुपए का इजाफ़ा नए कोड के कारण हुआ। आईसीआईसीआई बैंक ने 145 करोड़ रुपए, यस बैंक 155 करोड़, फेडरल बैंक 20.8 करोड़ और आरबीएल बैंक 32 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। बीमा कंपनियों में भी खर्च बढ़ा। एचडीएफसी लाइफ ने 106.02 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने 11.04 करोड़ रुपए और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 53.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त असर दर्ज किया। नए कोड के तहत बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाना अनिवार्य हो गया, जिससे ग्रेच्युटी, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी फंड में योगदान बढ़ा और कुल कर्मचारी लागत में इजाफ़ा हुआ। 21 नवंबर 2025 को चार कोड लागू किए गए, जिनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा शामिल हैं। 29 पुराने कानूनों को इनके अंतर्गत समेकित किया गया।

सोने का भाव 1.45 लाख, चांदी 3 लाख रुपए के पार

- अमेरिका की टैरिफ धमकी और सुरक्षित निवेश की मांग से कीमती धातुओं में आई तेजी

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी के वायदा कारोबार में सोमवार हो ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिका द्वारा नए टैरिफ लगाए जाने की धमकी के बीच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दोनों कीमती धातुएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना और चांदी दोनों के वायदा भाव ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते नजर आए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई। एमसीएक्स पर फरवरी डिलीवरी वाला सोने का बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट 804 रुपये की तेजी के साथ 1,43,321 रुपये पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,42,517 रुपये था। फिलहाल यह 1,909 रुपये की तेजी के साथ 1,44,426 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कारोबार के दौरान सोने ने 1,45,500 रुपये का दिन का उच्चतम स्तर छू लिया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। चांदी के वायदा भाव में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी 5,338 रुपये की तेजी के साथ 2,93,100 रुपये पर खुली। पिछले सत्र में इसका बंद भाव 2,87,762 रुपये था। फिलहाल चांदी 10,880 रुपये की बढ़त के साथ 2,98,642 रुपये के भाव पर कारोबार कर रही थी। कारोबार के दौरान चांदी पहली बार 3,01,315 रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी तेजी का रुख बना हुआ है। कॉमेक्स पर सोना 4,633.70 डॉलर प्रति औंस पर खुला और बाद में 4,600 डॉलर के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि इस साल का उच्चतम स्तर 4,663.70 डॉलर रहा। वहीं चांदी 90.60 डॉलर पर खुली और 94.36 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता के चलते कीमती धातुओं में आगे भी मजबूती बनी रह सकती है।

आम बजट 2026-27: नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 10-10.5 फीसदी रहने का अनुमान

- ऋण-जीडीपी अनुपात बनेगा प्रमुख राजकोषीय लक्ष्य

नई दिल्ली ।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 10 से 10.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण से यह संकेत मिला है। यह अनुमान ऐसे समय में सामने आया है जब चालू वित्त वर्ष में कम मुद्रास्फीति के कारण नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस माह जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, नॉमिनल जीडीपी 8 प्रतिशत की दर से बढ़कर 357 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि 9.5 प्रतिशत रही थी। वित्त मंत्रालय आगामी बजट में वित्त वर्ष 27 के अनुमानों के लिए वित्त वर्ष 26 के पहले अग्रिम आंकड़ों को आधार बनाएगा। हालांकि, 27 फरवरी को सांख्यिकी मंत्रालय वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान जारी करेगा, जो 2022-23 के नए आधार वर्ष पर आधारित होगा। इससे नॉमिनल जीडीपी के बजटीय अनुमानों में बदलाव संभव है। नॉमिनल जीडीपी का उपयोग ऋण-जीडीपी अनुपात, राजकोषीय घाटा और सरकारी राजस्व जैसे महत्वपूर्ण वृहद आर्थिक संकेतकों की गणना में किया जाता है। वित्त वर्ष 2026-27 एक अहम मोड़ साबित होगा, क्योंकि इसी वर्ष केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे के बजाय ऋण-जीडीपी अनुपात को प्राथमिक राजकोषीय लक्ष्य के रूप में अपनाएगी।

बजट 2026 में शादीशुदा जोड़ों के लिए जॉइंट टैक्सेशन की तैयारी

- पति-पत्नी अपनी कुल आय को जोड़कर टैक्स भर सकेंगे

नई दिल्ली ।

भारत में फिलहाल शादीशुदा होने पर कोई अलग टैक्स सुविधा नहीं है। पति और पत्नी दोनों को अलग पेन, अलग टैक्स स्लैब और अलग छूट मिलती है। यदि पत्नी की आय नहीं है, तो उसकी बुनियादी छूट व्यर्थ चली जाती है। इससे एक ही कमाने वाले परिवारों का टैक्स बोझ बढ़ जाता है। वित्त मंत्रालय अब वैकल्पिक जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लाने पर विचार कर रहा है। इसमें पति-पत्नी अपनी कुल आय को जोड़कर टैक्स भर सकेंगे। बुनियादी छूट सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि वर्तमान में एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए की छूट मिलती है, तो जॉइंट फाइलिंग में यह सीमा 6 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा, होम लोन ब्याज, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य कटौतियों को भी बेहतर तरीके से एडजस्ट किया जा सकेगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा एक ही कमाने वाले परिवारों को मिलेगा। मिडिल क्लास परिवारों का टैक्स बोझ कम होगा और उच्च आय वाले परिवारों को सरचार्ज में राहत मिल सकती है, क्योंकि वर्तमान 50 लाख रुपए से अधिक आय पर लगने वाला सरचार्ज जॉइंट फाइलिंग में 75 लाख रुपए या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। यदि दोनों पति-पत्नी कमाते हैं, तो उन्हें अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकती है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने इस प्रणाली की सिफारिश की है। प्रस्ताव यूनियन बजट 2026-27 में पेश किया जाएगा। बजट सेशन 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। अगर लागू हुआ, तो यह भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा।

कोहली स्थिति के अनुसार खेलते हैं, युवा क्रिकेटर उनसे सबक लें : विराट की शानदार इनिंग पर बोले गावस्कर

इंदौर (एजेंसी)। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के बैटिंग टेम्परमेंट की तारीफ करते हुए कहा है कि स्टार बल्लेबाज उम्मीद के मुताबिक खेलने के बजाय स्थिति के अनुसार अपने खेल को बदलने की क्षमता रखते हैं।

इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे के बाद जियोस्टार पर बातचीत में गावस्कर ने कहा कि कोहली की मानसिकता उन्हें कई समकालीन खिलाड़ियों से अलग बनाती है। गावस्कर ने कहा, 'उनके बारे में खास बात यह है कि वह किसी इमेज से बंधे नहीं हैं। बहुत से बल्लेबाज और गेंदबाज इस बात से बंधे होते हैं कि उन्हें कैसे देखा जाता है और उन्हें लगता है कि उन्हें उस इमेज पर खरा उतरना होगा। विराट ऐसे नहीं हैं। वह अपने काम पर ध्यान देते हैं और वह काम रन बनाना है।'

गावस्कर ने कहा, 'वह इस बात की उम्मीदों से बंधे नहीं हैं कि उन्हें कैसे खेलना चाहिए। वह स्थिति के अनुसार खेलते हैं। यही टेम्परमेंट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि दबाव में भी हार न मानने का कोहली का रवैया उनका एक खास गुण है जो कि उन्हें अन्य से भिन्न बनाता है। कोहली पर यह टिप्पणी सीरीज के निर्णायक मैच में 108 गेंदों पर 124 रन की उनकी शानदार पारी के बाद आई है। न्यूजीलैंड ने यह मैच 41 रन से जीतकर ऐतिहासिक 2-1 से वनडे सीरीज जीत ली जो कि 37 साल के इंतजार के बाद भारतीय धरती पर यह उनकी पहली सीरीज जीत थी।

उन्होंने कहा, 'आखिर तक भी वह कोशिश कर रहे थे। शायद दस्ताने थोड़े पसीने से गीले हो गए, ग्रिप थोड़ी ढीली हो गई, और इसीलिए बल्ले का मुंह घूम गया।' उन्होंने युवा क्रिकेटरों के लिए कोहली के इस रवैये को एक सबक के तौर पर भी बताया, और उनसे कहा कि वे पहले से बनी उम्मीदों के बजाय मैच की स्थितियों पर ध्यान दें।

गावस्कर ने ऑलराउंडर हर्षित राणा की निचले क्रम की बल्लेबाजी की भी तारीफ की और लक्ष्य का पीछा करने के अहम चरण में उनकी भूमिका की स्पष्टता की सराहना की। राणा ने 43 गेंदों पर 52 रन की जवाबी हमलावर पारी खेली और कोहली के साथ 99 रन की साझेदारी की, जिससे कुछ समय के लिए भारत की उम्मीदें फिर से जगीं।

गावस्कर ने कहा, 'उन्होंने बिल्कुल वैसे ही बल्लेबाजी की जैसे निचले क्रम के बल्लेबाज को करनी चाहिए, बिना किसी चिंता और बिना किसी उम्मीद के। उन्होंने कहा कि कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी के साथ राणा का शांत स्वभाव खास तौर पर प्रभावशाली था।'

नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया ओपन में 100वीं जीत, पेड्रो मार्टिनेंज को हराया

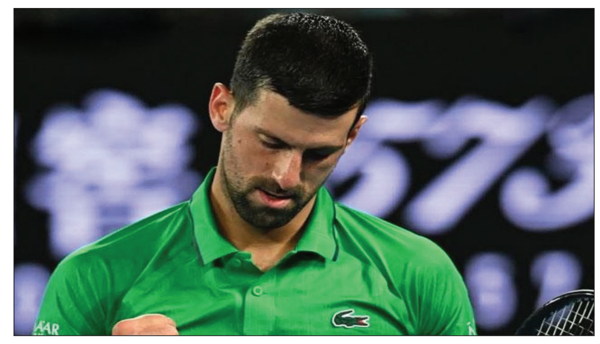

मेलबर्न (एजेंसी)। सार्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया ओपन में स्पेन के पेड्रो मार्टिनेंज को हराकर अपने करियर की 100वीं जीत दर्ज की। आज यहां पूर्व नंबर वन टेनिस खिलाड़ी जोकोविच ने पेड्रो मार्टिनेंज को 6-3, 6-2, 6-2 से हराकर शानदार प्रदर्शन करते हुए मेलबर्न पार्क में अपनी 100वीं करियर जीत हासिल की। रिकॉर्ड 10 बार के ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियन जोकोविच की अब टूर्नामेंट में रोजर फेडरर के 102 मैच जीतने के ऑल-टाइम रिकॉर्ड को तोड़ने पर नजर हैं। मैच के बाद जोकोविच ने कहा, 'मैं क्या कहूं। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। सेंचुरी बनाना बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा मैं शुरू में बहुत भाग्यशाली था कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सिखाया और गाइड किया कि मैं अपने करियर में लंबी रेस का घोड़ा बनूं, जल्दी थक न जाऊं, और जितना हो सके उतना लंबा करियर बनाऊं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं अभी भी इस स्तर पर खेल रहा हूं।' जोकोविच ने अब ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और रोलैंड गैरोस में 100 या उससे अधिक जीत दर्ज की हैं और वह तीन अलग-अलग बड़े टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इस जीत के साथ ही जोकोविच अपने लगातार 19वें ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे राउंड में पहुंच गये है। जहां जोकोविच का मुकाबला 23 साल के इटैलियन क्वालिफायर फ्रांसेस्को मेस्ट्रेली से होगा। डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने टेरेंस एटमेन को 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1 से हराकर किसी मेजर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत हासिल की।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में असफल रहे रोहित का शुभमन ने किया बचाव

इंदौर (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा है। इस सीरीज में भारतीय

टीम की हार का कारण सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का असफल होना रहा है जिससे एक बार फिर उनके फार्म पर सवाल उठे हैं। रोहित सीरीज के तीनों ही मैच में बड़ी पारी नहीं खेल पाये और केवल 61 रन ही बना पाये। तीसरे एकदिवसीय में भारतीय टीम को तीन सौ से अधिक रनों का लक्ष्य मिला था पर रोहित केवल 11 रन ही बना पाये।

सीरीज में उनका सबसे अधिक स्कोर 26 रन रहा है। वहीं टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रोहित का बचाव करते हुए कहा है कि वह इस सीरीज में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल पाये और ऐसा होता रहता है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। पिछले छह एकदिवसीय में उन्होंने चार बार 50 से ज्यादा रन बनाये थे पर इस बार वह इस लय को बनाये नहीं रख पाये। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय में रोहित केवल 11 रन ही बना पाये। इस प्रकार तीन एकदिवसीय मैचों में वह 26, 24 और 11 रन ही बना पाये। इसी कारण भारतीय टीम बड़े स्कोर नहीं बना पायी ओर उसे हार का सामना करना पड़ा। शुभमन ने मैच के बाद कहा,

÷मुझे लगता है कि वह अच्छे फॉर्म में हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका सीरीज तक उन्होंने रन बनाये हैं। इस सीरीज में वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाये पर मुझे लगता है कि उन्होंने पहले दो एकदिवसीय में टीम को अच्छी शुरुआत की थी। एक बल्लेबाज के तौर पर आप हमेशा चाहते हैं कि उन शुरुआतों को बड़े स्कोर में बदलें और शतक बनाएं हालांकि हर बार ऐसा संभव नहीं होता।'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 : बांग्लादेश के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, उठाया बड़ा कदम

मुम्बई (एजेंसी)। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 विश्व कप में भारत से अपने मैच स्थानांतरित करने की मांग की है और ऐसा ना होने पर टी20 वर्ल्ड कप से हटने की अपनी धमकी भी दी है। इस पर अब ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में भागीदारी को लेकर 21 जनवरी तक फैसला ले या सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट से बाहर होने को तैयार रहे। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अगले महीने भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित होने वाले इस इवेंट के लिए अपनी टीम की तैयारी रोक दी है।

टेलीकॉम एशिया ने PCB के टॉप सूत्रों के हवाले से बताया, 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नेशनल टीम की सभी तैयारियां रोक दी हैं और टीम मैनेजमेंट को प्लान के बारे में जानकारी दी गई है।' शनिवार को ढाका और इस्लामाबाद के बीच बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत न जाने के बांग्लादेश के फैसले

का पूरा समर्थन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PCB के चेयरमैन, मोहसिन नकवी, गठबंधन सरकार में गृह मंत्री के रूप में एक प्रमुख स्थान रखते हैं, एक सीनेटर के रूप में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है और विभिन्न मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की बातचीत से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से आगे कहा गया, 'नकवी शनिवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकारों के बीच बातचीत का हिस्सा थे, उन्होंने उनसे कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पूरा समर्थन करता है और अगर बांग्लादेश की मांगें उनकी इच्छा के अनुसार हल नहीं होती हैं तो वह इवेंट में अपनी भागीदारी पर फिर से विचार करेगा।' सूत्रों ने कहा कि PCB ने सरकार को सूचित किया है कि पाकिस्तान का हटना आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें सरकार की सलाह पेश करनी होगी और एक वैध कारण बताना होगा। यदि वे एक वैध कारण बताने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सदस्य भागीदारी समझौते का उल्लंघन करने के लिए दो मिलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है जिस पर सभी सदस्य ICC के साथ हस्ताक्षर करते हैं।

सूत्रों ने कहा कि PCB ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की भी पेशकश की है, अगर श्रीलंका में वेन्यू उपलब्ध नहीं हैं। बांग्लादेश ने मांग की है कि उनके मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और आगामी IPL 2026 के लिए अपने पेसर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 21 जनवरी तक बांग्लादेश के अनुरोध पर अंतिम फैसला लेगी। ये रिपोर्ट्स ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक मीटिंग के बाद आईं जिसमें दोनों पक्षों ने अपने-अपने रुख पर कायम रहे। बांग्लादेश ने ICC को यह भी सुझाव दिया था कि वह अपनी टीम को ग्रुप B में भेजने पर विचार करे। आयरलैंड के साथ जगह बदल ले, जो अपने ग्रुप मैच श्रीलंका में खेलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ICC ने आयरलैंड को आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

सृष्टि किरण ने जीता आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स जे30 का खिताब, पूरी की हैट्रिक

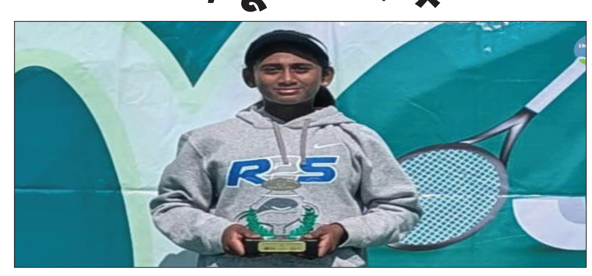

बेंगलुरु । भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण ने मेक्सिको के हुआमांटला में हुए आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स जे30 टूर्नामेंट में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता ।मेक्सिको के हुआमांटला में 12 से 18 जनवरी तक चली इस चैंपियनशिप में बेंगलुरु की 13 साल की सृष्टि ने घरेलू पसंदीदा तमारा हरमन (मेक्सिको) को 6-4, 6-4 से हराकर आईटीएफ खिताबों की शानदार हैट्रिक पूरी की। इससे पहले ड्रॉ में उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार वापसी करते हुए लगातार 10 गेम जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की और 2-4 से पीछे होने के बाद 16 साल की घरेलू पसंदीदा मिरांडा सोफिया एस्कैमिला मोरालेस (मेक्सिको) को 6-4, 6-0 से हराया।

टी20 विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाना है लक्ष्य : कमिंस

मेलबर्न ।ऑस्ट्रेलिाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि उनका लक्ष्य नये साल में भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्कप मे बेहतर प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलाना है। कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य तेज गेंदबाज हैं और कार्यभार प्रबंधन के तहत ही उन्हें एशेज सीरीज के बचे हुए दो टेस्ट मैचों से बाहर रखा गया है। कमिंस चोटिल होने के कारण पहले दो टेस्ट में शामिल नहीं थे। मेजबान टीम ने पहले ही सीरीज 3-0 से जीत ली है जिससे देखते हुए कमिंस को उतारकर टीम जोखिम नहीं लेना चाहती है। कमिंस को जून जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे पर कमर में चोट लगी थी। जिससे देखते हुए टीम प्रबंधन उनपर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता। वहीं कमिंस ने कहा कि अब आराम करने के बाद उन्हें पहले से बेहतर लग रहा है। साथ ही कहा कि कुछ सप्ताह पहले ही कमर की चोट से उबरा हूं तो लगातार दो टेस्ट खेलना जोखिमभरा रहता। अब टी20 विश्व कप से पहले कुछ आराम करूंगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 विश्व कप में पहला मैच 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड से खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने हाल में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है। जिसके कारण कमिंस टीम के प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं।

इंडोनेशिया मास्टर्स 2026: पीवी सिंधु की अगुआई में भारत को बड़ी उम्मीद

जकार्ता (एजेंसी)। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु इंडिया ओपन में पहले दौर में मिली निराशाजनक हार को पीछे छोड़ते हुए इंडोनेशिया मास्टर्स 2026 में भारत की चुनौती की अगुआई करेंगी। बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 स्तर का यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट मंगलवार से शुरू हो रहा है और सीजन की शुरुआत में ही खिलाड़ियों के लिए अहम पड़ाव माना जा रहा है।

नई दिल्ली में पिछले सप्ताह हुए इंडिया ओपन में शुरुआती दौर में बाहर होने के बाद सिंधु की नजरें इस टूर्नामेंट में लय हासिल करने पर टिकी होंगी। हालांकि, इस महीने की शुरुआत में खेले गए मलेशिया ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचकर उन्होंने अपनी फॉर्म के संकेत जरूर दिए थे। ऐसे में जकार्ता में वह मजबूत वापसी की कोशिश करेंगी।

महिला एकल में भारत की मजबूत मौजूदगी

महिला एकल के पहले दौर में पीवी सिंधु का सामना जापान की मनामी सुइज़ु से होगा, जो उनसे रैंकिंग में नीचे हैं। इस वर्ग में भारत की अच्छी-खासी भागीदारी देखने को मिलेगी। सिंधु के अलावा मालविका बंसोड़, तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा भी मुख्य ड्रॉ में उतरेंगी। हालांकि उन्नति हुड्डा के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि पहले ही दौर में उनका मुकाबला चीन की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चेन यूफेई से तय हुआ है।

पुरुष एकल में लक्ष्य सेन से उम्मीदें

पुरुष एकल में भारत की सबसे बड़ी उम्मीदें मौजूदा विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर काबिज लक्ष्य सेन से होंगी। लक्ष्य ने हाल ही में इंडिया ओपन में क्वार्टरफाइनल तक का सफर तय किया था और उसी लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनके अलावा पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, थरुण मन्नेपल्ली और आयुष शेट्टी भी टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वर्ग में थाईलैंड के पेरिस ओलंपिक 2024 के रजत पदक विजेता कुनलावुत वितिदसर्न शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के रूप में उतरेंगे।

डबल्स में सीमित लेकिन अहम भागीदारी

डबल्स स्पर्धाओं में भारत की मौजूदगी अपेक्षाकृत सीमित है। पुरुष युगल में हरिहरन अमसकरुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी ही मुख्य ड्रॉ में नजर आएगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला-तनिषा क्रास्टो और रोहन कपूर-रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं महिला युगल में रश्मि गणेश और सानिया सिकंदर की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।

डेनियल मेदवेदेव ने जेस्पर डी जोंग को हराया, ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे

मेलबर्न । रूस के डेनियल मेदवेदेव ने सोमवार को नीदलैंड के जेस्पर डी जोंग को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली हैं। आज यहां मेलबर्न पार्क के मार्गरेट कोर्ट एरिना में 11वीं सीड मेदवेदेव ने नीदरलैंड के खिलाड़ी जेस्पर डी जोंग के खिलाफ दो घंटे 53 मिनट तक चले मुकाबले में 7-5 6-2 7-6 (7-2) की जीत दर्ज की। मेदवेदेव अब अगले मैच में फ्रांस के क्वेंटिन हैलिस का सामना करेंगे। मैच के बाद मेदवेदेव ने कहा, 'अब तक मैं यह अच्छा कर रहा हूं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बस कोर्ट पर उतना ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा हूं जितना मैं जिदगी में हूं। पिछले साल जो हुआ, सो हुआ, और यह ठीक है। यह करियर का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है।'

आईपीएल में प्लेऑफ की प्रबल दावेदार रहेंगी ये टीमें : अमित मिश्रा

नई दिल्ली । पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने कहा है कि कोलकाता नाइटराइडर्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ में पहुंच सकती हैं। इस पूर्व स्पिनर के अनुसार गुजरात टाइटंस को भी खिताबी दौड़ में कमजोर नहीं माना जा सकता है। इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, केकेआर, एमआई, एसआरएच, आरसीबी और जीटी। मेरे ख?याल से इन पांच में से कोई चार टीमें ए?लेऑफ में पहुंचेगी। वहीं अमित ने चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) को खिताबी दावेदार नहीं माना है जिससे सभी को हैरानी हुई है। सीएसके पांच बार की विवेता रही है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी ने नीलामी से पहले ही पसंदीदा खिलाड़ियों का रिटेन कर अपनी टीम मजबूत की है। वहीं अन्य टीमों ने मिनी नीलामी के जरिये टीम की ताकत बढ़ायी है। केकेआर ने कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा जबकि सनराइजर्स ने लियाम लिविंगस्?टन को 13 करोड़ रुपये में खरीदा।आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से होगी और फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा।

विश्वकप में खेलना सभी का सपना रहता है : सिराज

मुम्बई । अगले माह 7 फरवरी से होने वाले टी20 विश्वकप के लिए इस बार भारतीय टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिली है। सिराज हालांकि इससे निराश नहीं हैं और उनका कहना है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगी। सिराज ने कहा कि वह भी इस टूर्नामेंट में खेलने चाहते थे क्योंकि सभी का सपना विश्वकप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में देश की ओर से खेलना रहता है। विश्वकप इस बार भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह संभालेंगे। उनका साथ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा देंगे। सिराज ने कहा, मैंने पिछले ञ20 विश्वकप में खेला था पर इस बार अवसर नहीं मिला। एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सपना विश्व कप में खेलकर टीम की जीत में योगदान देना रहता है। उन्होंने कहा कि विश्कप के लिए हमारी टीम अच्छी है। वह अच्छे फार्म में भी है। जिससे उम्मीद है कि टीम टूर्नामेंट जीतेगी। वहीं सिराज ने कार्यभार प्रबंधन को भी जरुरी बताया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान आराम दिया गया था। उन्होंने कहा, मुझे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली एकदिवसीय सीरीज से आराम दिया गया था क्योंकि मैंने गुवाहाटी में उनके खिलाफ दूसरे टेस्ट में 40 ओवर फेंके थे। मैं टीम से बाहर नहीं हुआ हूं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में एकदिवसीय सीरीज खेली, फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुझे आराम दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तेज गेंदबाज को पर्याप्त आराम बहुत जरूरी है। मैं लगातार टेस्ट मैच खेल रहा हूं। ऐसे में आपको तरोताजा होने के लिए आराम की जरूरत होती है।

उसेन बोल्ट का रिटायरमेंट से वापसी का मन, LA 2028 ओलंपिक्स में इस खेल में हिस्सा लेने की इच्छा जताई

नई दिल्ली (एजेंसी)। जमैका के महान धावक और दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले उसेन बोल्ट ने खेल जगत को चौंकाने वाला संकेत दिया है। बोल्ट ने कहा है कि वह 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में वापसी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार ट्रैक पर नहीं, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर। 128 साल बाद ओलंपिक में लौट रहे क्रिकेट के साथ बोल्ट की यह इच्छा खेल प्रेमियों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।

क्रिकेट के साथ बोल्ट का पुराना रिश्ता

बहुत कम लोग जानते हैं कि एथलेटिक्स से पहले उसेन बोल्ट का पहला खेल प्रेम क्रिकेट था। कैरेबियन संस्कृति में पले-बढ़े बोल्ट बचपन में एक तेज गेंदबाज के रूप में पहचाने जाते थे। स्कूल के दिनों में उनके क्रिकेट कोच ने ही उन्हें ट्रैक एंड फील्ड आजमाने की सलाह दी थी, जिसने आगे चलकर खेल इतिहास को नई दिशा दे दी। हालांकि बोल्ट ने एथलेटिक्स में जो मुकाम हासिल किया, उसके बावजूद क्रिकेट के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ।

LA 2028 में क्रिकेट की ऐतिहासिक वापसी

क्रिकेट 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक के ज़रिये 128 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक मंच पर लौटेगा। आखिरी बार यह खेल 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था, जहां ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। LA28 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी। हर टूर्नामेंट के लिए 90 खिलाड़ियों का कोटा तय किया गया है, जिससे प्रत्येक देश 15 खिलाड़ियों की टीम उतार सकेगा।

'अगर कॉल आया, तो तैयार हूं'

एस्क्वायर मैगज़ीन से बातचीत में बोल्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वह पेशेवर खेल से संतुष्ट होकर संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अगर जमैका क्रिकेट बोर्ड की ओर से उन्हें मौका मिलता है, तो वह पीछे नहीं हटेंगे।उनके इस बयान ने फैंस की कल्पनाओं को नई उड़ान दे दी है, खासकर तब जब क्रिकेट ओलंपिक में नई शुरुआत कर रहा है।

एथलेटिक्स में बोल्ट की बेमिसाल विरासत

उसेन बोल्ट को अब तक का सबसे महान स्प्रिंटर माना जाता है। उनके नाम आठ ओलंपिक स्वर्ण पदक और 11 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड हैं। उन्होंने 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक में लगातार 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में जीत दर्ज की। 2009 बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में बनाए गए उनके 100 मीटर (9.58 सेकंड) और 200 मीटर (19.19 सेकंड) के रिकॉर्ड आज भी अटूट हैं।

क्रिकेट से जुड़े हालिया अनुभव

बोल्ट हाल के वर्षों में क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। वह ञ20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एंबेसडर रहे, जो अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला गया था। इसके अलावा उन्होंने भारत में युवराज सिंह और हरभजन सिंह के साथ एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भी हिस्सा लिया था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

ब्रिटेन : चीन की नई दूतावास योजना के विरोध में प्रदर्शन

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में चीन के नए बड़े दूतावास की योजना के विरोध में प्रदर्शन हुआ। मुख्य विपक्षी नेता केमी बेडेनोच ने सरकार से इसे रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि चीन ने ब्रिटिश नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रदर्शनकारियों ने 'नो चाइना मेगा एंबेसी' के नारे लगाए। सरकार को फैसला करना है कि दूतावास बनेगा या नहीं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह दूतावास जासूसी और निर्वासित चीन विरोधियों पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने योजना को कम जोखिम मानते हुए मंजूरी दी।

सऊदी अरब में मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस, दी श्रद्धांजलि

रियाद, एजेंसी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों को उनकी निःस्वार्थ सेवा, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सऊदी में भारतीय राजदूत सुहेल एजाज खान ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारतीय टुकड़ियों के अंतरराष्ट्रीय योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य, भारतीय समुदाय के सदस्य, रियाद के भारतीय स्कूलों के छात्र और दूतावास के अधिकारी शामिल हुए।

युगांडा पुलिस ने विपक्षी नेता वाइन की गिरफ्तारी का किया खंडन

कंपाला, एजेंसी। युगांडा पुलिस ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया, जिनमें कहा गया कि बृहस्पतिवार को हुए तनावपूर्ण चुनाव के दौरान मुख्य विपक्षी उम्मीदवार बॉबी वाइन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन रिपोर्ट्स को फर्जी और भड़काऊ करार दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। युगांडा के 81 वर्षीय राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी सातवें कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती नतीजों में 70 फीसदी से ज्यादा समर्थन के साथ आगे चल रहे हैं।

सर्बिया : भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन

नोवी साड, एजेंसी। सर्बिया में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर एकत्र हुए। विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रपति अलेक्जांडर वुचिक के खिलाफ अपनी सबसे आंदोलन का नया चरण शुरू किया। पिछले एक साल से जारी प्रदर्शन ने उनके सत्तावादी शासन को हिलाकर रख दिया है। नोवी साड शहर में प्रदर्शनकारियों ने 'चोर' के नारे लगाए और कहा कि सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। उनका कहना था कि इसी भ्रष्टाचार की वजह से नवंबर 2024 में ट्रेन स्टेशन पर हादसा हुआ, जिसमें 16 लोग मरे। इस हादसे के कारण पूरे देश से सरकार बदलने की मांग तेज हुई। राष्ट्रपति वुचिक ने छात्रों की मांग के बावजूद जल्दी चुनाव कराने से इनकार किया। कई लोग गिरफ्तार हुए, कई लोगों को नौकरी खोना पड़ी और सरकार का विरोध करने पर दबाव झेलना पड़ा। छात्रों ने कहा कि अब वे सरकार का समाधान देंगे।

ईरान : तुर्किये की सीमा पार कर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे लोग

तेहरान, एजेंसी। ईरान में आठ जनवरी से इंटरनेट पर पाबंदी है। लोग तुर्किये की सीमा पार कर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन अब थम गए है, लेकिन इंटरनेट न होने से लोगों को काम करने में मुश्किल हो रही है। ईरानी बिना वीजा तुर्किये जा सकते हैं। कुछ लोग छोटे सफर कर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग ईरान से तुर्की सामान बेचकर पैसे जुटाते हैं। सामी नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि उनका काम ई-कॉमर्स पर है, इसलिए उन्हें इंटरनेट के लिए तुर्किये आना पड़ता है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उन्हें परिवार और नौकरी के लिए वापस ईरान लौटना पड़ता है। 28 दिसंबर से शुरू हुए विरोध में कम से कम 3,095 लोग मारे गए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शनों से खुद से अलग मानते हैं और इन्हें अमेरिका-इजराइल की साजिश की बातें मानते हैं।

नेपाल : सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में देउबा गुट, चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी

काठमांडो, एजेंसी। नेपाली कांग्रेस का शेरबहादुर देउबा गुट पार्टी की आधिकारिकता से जुड़े निर्वाचन आयोग के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। देउबा गुट ने आयोग के फैसले को पार्टी विधान और संविधान के खिलाफ बताते हुए उसके विरुद्ध कानूनी, सांविधानिक और राजनीतिक स्तर पर कदम उठाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा में पूर्व सभापति शेर बहादुर देउबा पक्ष की नेता सहभागी बैठक के बाद यह एलान किया गया। बैठक में पूर्व सभापति शेरबहादुर देउबा पक्ष के नेता शामिल हुए।

इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा विमान लापता

पहाड़ी इलाके में रडार से गायब, सर्च ऑपरेशन जारी, सरकार से जुड़े लोग सवार थे

जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशिया में 11 लोगों को ले जा रहा एक यात्री विमान शनिवार को रडार से गायब हो गया। विमान जावा द्वीप से सुलावेसी द्वीप की ओर जा रहा था और पहाड़ी इलाके में पहुंचते ही ग्राउंड कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। अधिकारियों के मुताबिक, विमान में 8 क्रू मेंबर और 3 यात्री सवार थे। इसके बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अभी किसी के जीवित या मृत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हादसे के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशियाई सरकार में मंत्री ने कहा कि विमान में समुद्री मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय के तीन कर्मचारी सवार थे। वे इलाके में संसाधनों की हवाई निगरानी के मिशन पर थे। लापता हुआ टर्बोप्रॉप एटीआर42-500 विमान इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट का था। यह विमान योग्याकार्ता से दक्षिण सुलावेसी की राजधानी की ओर जा रहा था। परिवहन मंत्रालय की प्रवक्ता एंडाह पुर्नामा सारी के मुताबिक, विमान दोपहर 1:17 बजे (05:17 जीएमटी) मारोस जिले के लेआंग-लेआंग इलाके में आखिरी बार रडार पर देखा गया। सारी ने बताया कि लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को अप्रोच एलाइनमेंट ठीक करने

के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद रेडियो संपर्क टूट गया। इसके बाद कंट्रोल टावर ने इमरजेंसी डिस्टेस फेज घोषित किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

सर्च ऑपरेशन के लिए सेना-ड्रोन तैनात : विमान जिस इलाके में लापता हुआ, वह पहाड़ी और घने जंगलों वाला क्षेत्र है। यहां पहुंचना रेस्क्यू टीमों के लिए बड़ी चुनौती है। सर्च ऑपरेशन के लिए एयरफोर्स के हेलिकॉप्टर, ड्रोन और ग्राउंड यूनिट्स को लगाया गया है। दक्षिण सुलावेसी के हसनुद्दीन मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल बांगुन नवोको ने इसकी पुष्टि की। इस बीच माउंट बुलुसराउंग इलाके में ट्रैकिंग कर रहे कुछ हाइकर्स ने पहाड़ पर बिखरा मलबा, विमान जैसा लोगो और आग जलने की सूचना दी है। मेजर जनरल नवोको के मुताबिक, इन सूचनाओं की पुष्टि के लिए रेस्क्यू टीमें मौके तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय इलाके में बादल थे, लेकिन विजिबिलिटी करीब 8 किलोमीटर थी। हालांकि, खड़ी पहाड़ियां और घना जंगल रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रहे हैं।

कौन थे विमान में सवार : दक्षिण सुलावेसी के हसनुद्दीन सैन्य कमांडर मेजर जनरल बंगुन नावोको ने कहा कि इस बारे में सूचना अधिकारियों को दे दी गई है और बचाव दल उक्त क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसकी पुष्टि कर रहे हैं। सारी ने कहा कि एटीसी के अंतिम निर्देशों के बाद, रेडियो संपर्क टूट गया और नियंत्रकों ने आपातकालीन संकट की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बचाव दल ने अपनी खोज उन पहाड़ों के आसपास केंद्रित की, जहां माना जाता है कि विमान सुल्तान हसनुद्दीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के अपने मार्ग से भटक गया था। उन्होंने बताया कि विमान में चालक दल के आठ सदस्य और समुद्री मामलों और मत्स्य मंत्रालय के तीन यात्री सवार थे।

चूना-पत्थर की पहाड़ियों से घिरा है लेआंग-लेआंग इलाका : लेआंग-लेआंग इलाका चूना-पत्थर की पहाड़ियां, गुफाएं और घने जंगल हैं। यह बंटिमुरुंग-बुलुसाराउंग नेशनल पार्क का हिस्सा माना जाता है। यह मुश्किल रास्तों से भरा इलाका है, जहां संकरी घाटियां और ऊंची चट्टानें हैं। इंडोनेशिया में सितंबर 2025 में भी 2 हादसे हुए थे एएफपी के मुताबिक, दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद विशाल द्वीपसमूह इंडोनेशिया अपने सैंकड़ों द्वीपों को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर हवाई परिवहन पर निर्भर है। हालांकि, देश का विमानन सुरक्षा रिकॉर्ड कमजोर रहा है और हाल के महीनों में कई हादसे हुए हैं। 1 सितंबर 2025 में, दक्षिण कालीमंतान राज्य से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक बीके117 डी3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद 10 सितंबर 2025 को पापुआ के इलागा जिले में एक और यूरोकॉप्टर एएस350बी3+ हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से 4 लोगों की मौत हो गई थी।

इराक के ऐन अल-असद बेस से पूरी तरह हटी अमेरिकी सेना

बगदाद, एजेंसी। इराकी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अमेरिका ने पश्चिमी इराक में एक प्रमुख एयर बेस से अपनी सेना पूरी तरह हटा ली है। इराक सरकार के साथ समझौते के तहत सैनिकों की यह वापसी हुई। वॉशिंगटन और बगदाद ने 2024 में यह तय किया था कि अमेरिकी के नेतृत्व में बनाई गई सेना सितंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से ऐन अल-असद बेस पीछे हट जाएगी। यह सेना आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) से खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार की गई थी। समझौते के तहत अमेरिकी सैन्यकर्मियों को उन बेस से हटना था, जहां वह तैनात थे। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद क्या हुआ अब एयर बेस से सभी अमेरिकी सैनिक और कर्मचारी वापस चले गए हैं। अमेरिकी सेना के पीछे हटने के बाद इराकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर राशिद यारल्लाह ने बेस में सभी सैन्य इकाइयों को काम और जिम्मेदारियां सौंपीं। यारल्लाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रयास तेज करें, संयुक्त कार्य में सुधार लाएं और बेस में तैनात इकाइयों के बीच तालमेल बढ़ाएं।

उन्होंने बेस की क्षमताओं और रणनीतिक स्थिति का पूरा उपयोग करने का भी आदेश दिया। इराकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने क्या जानकारी दी? रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी अमेरिकी सैनिक बेस से चले गए हैं और उन्होंने सभी अमेरिकी उपकरण भी हटा लिए हैं। अधिकारी को सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने की अनुमति नहीं थी, जिस कारण नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने यह जानकारी दी। अमेरिकी सेना की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, अमेरिकी सेना अभी भी इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र और पड़ोसी सीरिया में मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी देश में गैर-सरकारी सशस्त्र समूहों को हथियार जमा करने के मुद्दे में सरकार की स्थिति को मजबूत कर सकती है। कुछ समूह अब तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का उपयोग अपने हथियार रखने का औचित्य साबित करने के लिए करते रहे हैं। अल-सुदानी ने जुलाई में एसोसिएटेड प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि एक बार अमेरिकी सेना की वापसी हो जाने के बाद किसी भी समूह को राज्य के नियंत्रण के बाहर हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

कराची के मॉल में लगी भीषण आग, हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत; कई घायल

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के कराची में शनिवार देर रात एक शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने से तीन लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि शनिवार देर रात कराची के एमए जिन्ना रोड स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के कार्यकारी निदेशक डॉ. साबिर मेमन ने बताया कि तीन शव अस्पताल लाए गए थे। उन्होंने कहा कि तीनों ही लोग अस्पताल लाए जाने के समय मृत थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण के पुलिस उप महानिरीक्षक सैयद असद रजा ने कहा कि इस घटना में कम से कम सात अन्य लोग घायल हुए हैं।

आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका : बचाव दल के अधिकारियों ने बताया कि आग ऊंची व्यावसायिक इमारत के भूतल पर स्थित दुकानों में लगी, जबकि ऊपरी मंजिलों पर कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव दल के प्रवक्ता हसनुल हसीब खान ने बताया कि छह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आग बुझाने के अभियान में कई दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। गार्डन सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी मोहसिन रजा ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। जो बाद में पूरे शॉपिंग मॉल में फैल गई। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों की सात गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और सिविल अस्पताल के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सिंध के राज्यपाल कामरान टेसोरी ने घटना पर चिंता व्यक्त की और अपने कार्यालय से जारी एक बयान में संबंधित अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों में तत्काल तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने घटना और आग बुझाने के प्रयासों पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी और व्यापारियों एवं प्रभावित लोगों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

'यूक्रेन और ग्रीनलैंड पर किसी भी धमकी से नहीं डरेंगे'; ट्रंप की 10% टैरिफ चेतावनी पर मैक्रों का जवाब

पेरिस/ब्रुसेल्स , एजेंसी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दी गई टैरिफ धमकियों पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। मैक्रों ने साफ शब्दों में कहा कि यूक्रेन, ग्रीनलैंड या दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव फ्रांस को अपने सिद्धांतों से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता।

यूरोप की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यूरोप की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा और यदि टैरिफ लगाए जाते हैं तो यूरोपीय देश एकजुट और समन्वित जवाब देंगे। मैक्रों ने कहा कोई भी धमकी या डर हमें प्रभावित नहीं कर सकता न

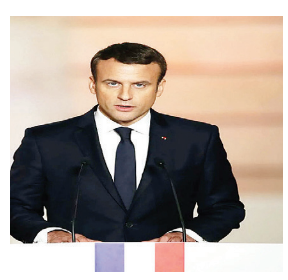

यूक्रेन में, न ग्रीनलैंड में और न ही दुनिया के किसी अन्य हिस्से में। टैरिफ की धमकियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फ्रांस का यूक्रेन को समर्थन और ग्रीनलैंड में डेनमार्क द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास में भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित है। मैक्रों के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र और यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा फ्रांस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है।

अमेरिका की टैरिफ धमकी गलत- कीर स्टारमर : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की ओर से यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी को पूरी तरह गलत बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टारमर ने कहा कि नाटो सहयोगियों की सामूहिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर अपने ही सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी प्रशासन के साथ उठाएगा। साथ ही, स्टारमर ने दोहराया कि ब्रिटेन के अनुसार ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों का है। ट्रंप की धमकी पर यूरोपीय संघ प्रमुख ने क्या कहा? इस बीच, यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका की संभावित टैरिफ नीति को लेकर गहरी चिंता जताई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चेतावनी दी कि इस तरह के टैरिफ ट्रांस-अटलांटिक संबंधों को कमजोर कर सकते हैं और एक खतरनाक आर्थिक गिरावट को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता जताते हुए कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल स्तंभ हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों की सैन्य मौजूदगी पहले से नियोजित डेनिश अभ्यास का हिस्सा है और इससे किसी देश को कोई खतरा नहीं है। ईयू ने इस मुद्दे पर रविवार को आपात बैठक बुलाने का भी एलान किया है, जिसमें अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ पर सामूहिक रणनीति पर चर्चा होगी।

मस्क के बच्चे की मां का ग्रोक से बनी तस्वीरों के विरुद्ध मुकदमा

वाशिंगटन, एजेंसी। एलन मस्क के एक बच्चे की मां एशले सेंट क्लेयर (27) ने उनकी एआई कंपनी एक्सएआई पर मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि कंपनी के ग्रोक चैटबॉट ने यूजरों को उनकी यौन शोषणकारी डीपफेक तस्वीरें बनाने की अनुमति दी, जिससे उन्हें अपमान और मानसिक पीड़ा हुई है। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि इन तस्वीरों में उनकी 14 साल की उम्र की पूरी तरह से कपड़े पहनी हुई तस्वीर को संपादित कर उन्हें बिकिनी में दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य तस्वीरों में उन्हें वयस्क के रूप में यौनेत्तेजक मुद्राओं में और स्वास्तिक चिन्ह वाली बिकिनी पहने हुए दिखाया गया है। सेंट क्लेयर यहूदी हैं और राजनीति रणनीतिकार तथा लेखक हैं। ग्रोक मस्क के सोशल मीडिया मंच एक्स पर उपलब्ध है। एक्सएआई के वकीलों ने इस संबंध में

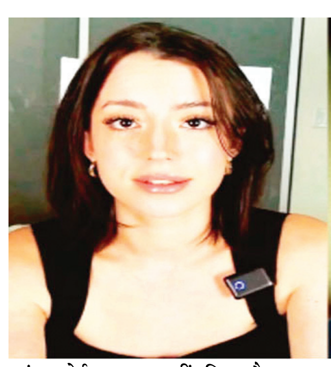

तुरंत कोई जवाब नहीं दिया है। यह मुकदमा भी मस्क को झटका है। सेंट क्लेयर ने बताया कि पिछले साल जब ये डीपफेक तस्वीरें सामने आने लगीं तो उन्होंने ङ्ग प्लेटफॉर्म को इसकी सूचना दी और इन्हें हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म ने पहले जवाब दिया कि ये तस्वीरें उसकी नीतियों का उल्लंघन नहीं करतीं। फिर उसने वादा किया कि उसकी सहमति के बिना उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल या उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेंट क्लेयर, मस्क के 16 महीने के बेटे रोमुलस की मां हैं। वह न्यूयॉर्क शहर में रहती हैं, जहां उन्होंने राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। वह कथित मानसिक पीड़ा और अन्य दावों के लिए मुआवजे के तौर पर एक अज्ञात राशि की मांग कर रही हैं, साथ ही अदालत से यह आदेश देने की भी मांग कर रही हैं कि ॠद्ध को उनके और डीपफेक वीडियो बनाने से तुरंत रोका जाए। मस्क ने ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट से मांगा 134 अरब डॉलर का हर्जाना संघीय कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार, मस्क ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट से 134 अरब डॉलर तक का हर्जाना मांग रहे हैं। उनका तर्क है कि एआई स्टार्टअप को उनके शुरुआती समर्थन से कंपनियों को जो गलत तरीके से लाभ मिला है। मस्क ने याचिका में कहा, 2015 से ओपनएआई के सह-संस्थापक के रूप में उनके योगदान से 65.5 अरब डॉलर से 109.4 अरब डॉलर का लाभ हुआ जबकि माइक्रोसॉफ्ट को 13.3 अरब डॉलर से 25.1 अरब डॉलर का लाभ हुआ।

ग्रीनलैंड में प्रधानमंत्री की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

नुउक , एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के बयानों के खिलाफ ग्रीनलैंड में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है. शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी नूक की सड़कों पर उतरे और अमेरिका के संभावित कब्जे के दावों के खिलाफ आवाज बुलंद की. प्रदर्शनकारियों की अगुवाई खुद ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने की. हाथों में झंडे और बैनर लेकर लोग अमेरिकी कॉन्सुलेट की ओर मार्च करते नजर आए. प्रदर्शन के दौरान साफ संदेश दिया गया कि ग्रीनलैंड को अपने भविष्य का फैसला खुद करने दिया जाए. प्रदर्शनकारी उस नए निर्माणाधीन ब्लॉक के पास से गुजरे, जहां अमेरिका अपने कॉन्सुलेट को शिफ्ट करने की योजना बना रहा है. फिलहाल, अमेरिकी कॉन्सुलेट एक लाल रंग की लकड़ी की इमारत में चलता है, जहां सिर्फ चार कर्मचारी तैनात हैं. ट्रंप का दावा- अमेरिकी सुरक्षा के लिए अहम है ग्रीनलैंड राष्ट्रपति ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और वहां मौजूद बड़े खनिज भंडार अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं. ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया जा सकता. इसी सप्ताह डेनमार्क के अनुरोध पर यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड में सैन्य कर्मियों की तैनाती की है, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं. नाटो सहयोगियों के बीच राजनयिक संकट ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के बार-बार दिए गए बयानों ने अमेरिका और डेनमार्क के बीच राजनयिक संकट पैदा कर दिया है. दोनों देश नाटो के संस्थापक सदस्य हैं. ट्रंप के बयानों की यूरोप में तीखी आलोचना हो रही है. ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57 हजार है. यह इलाका सदियों तक कोपेनहेगन से शासित रहा है. वर्ष 1979 के बाद से ग्रीनलैंड को काफी हद तक स्वायत्तता मिली है, लेकिन यह अब भी डेनमार्क का हिस्सा है. रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है और प्रशासन का बड़ा खर्च भी वही उठाता है. ट्रंप के करीबी स्टीफन मिलर का तीखा बयान इस विवाद को और हवा तब मिली जब व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ (पॉलिसी) स्टीफन मिलर ने ट्रंप के दावे को दोहराते हुए कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता. फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम हैनिटी में मिलर ने कहा, किसी इलाके पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि आप उसकी रक्षा कर सकें, उसे बेहतर बना सकें और वहां रह सकें. डेनमार्क इन तीनों ही कसौटियों पर फेल रहा है. डेनमार्क ने साफ किया है कि वह ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो की ज्यादा स्थायी और मजबूत मौजूदगी की योजना पर आगे बढ़ रहा है।

ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध पड़ा महंगा, 8 देशों पर फूटा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम

वाशिंगटन, एजेंसी। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना पर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने वाले 8 देशों पर अमेरिका ने 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 10 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अगर ग्रीनलैंड की खरीद वाली डील नहीं पूरी हो पाती है तो इस टैरिफ को बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया जाएगा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच कांग्रेस के एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने समर्थन का आश्वासन देने की कोशिश की। ट्रंप ने धमकी दी है कि आर्कटिक के रणनीतिक द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण का समर्थन नहीं करने पर कड़े शुल्क लगाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल के नेता और डेलावेयर से डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर मौजूदा बयानबाजी से डेनमार्क में चिंता का माहौल है। उन्होंने कहा कि वह हालात को शांत करना चाहते हैं।

कोपेनहेगन में कून्स ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि डेनमार्क के लोग अमेरिकी लोगों में अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे।' उन्होंने कहा कि अमेरिका डेनमार्क और नाटो के प्रति 'उन सभी कार्यों के लिए सम्मान रखता है जो हमने साथ मिलकर किए हैं।'

उनकी टिप्पणियां 'व्हाइट हाउस' से आ रही टिप्पणियों से बिल्कुल विपरीत हैं। ट्रंप ने बार-बार यह दावा करके अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की अपनी मांगों को सही ठहराने की कोशिश की है कि चीन और रूस की ग्रीनलैंड पर नजर है, जहां महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल अप्रयुक्त भंडार मौजूद हैं। 'व्हाइट हाउस' ने जबरन इस क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। कून्स ने कहा, ''ग्रीनलैंड को

फिलहाल कोई सुरक्षा खतरा नहीं है।'' ट्रंप कई महीनों से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्द्ध-स्वायत्त क्षेत्र है। उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि ग्रीनलैंड का अमेरिकी नियंत्रण में न होना 'अस्वीकार्य' होगा।

'ग्रीनलैंड की सुरक्षा पश्चिम के लिए अहम' : जॉन बोल्टन ने कहा है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा पश्चिमी देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से न केवल अमेरिका बल्कि पूरे पश्चिम के लिए सुरक्षा और स्थिरता का केंद्र है। बोल्टन ने ट्रंप के हालिया बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका के सहयोगियों पर टैरिफ की धमकियां देना, ग्रीनलैंड के बदले में, आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना और भी कठिन बना देता है। उन्होंने कहा मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि एक सुरक्षित ग्रीनलैंड निस्संदेह पश्चिम के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ट्रंप का हालिया विचित्र बयान, जिसमें ग्रीनलैंड के लिए सहयोगियों को टैरिफ की धमकी दी गई, आर्कटिक में स्थिरता और सुरक्षा की चुनौती को और बढ़ा देता है।

ट्रंप ने ग्रीनलैंड विवाद पर यूरोप को 25% टैरिफ की धमकी दी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड पर 1 फरवरी, 2026 से 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून, 2026 से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका ने दशकों तक डेनमार्क और यूरोपीय देशों को टैरिफ या किसी अतिरिक्त भुगतान के बिना सब्सिडी दी है और अब डेनमार्क को वापस देने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन और रूस ग्रीनलैंड पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जबकि डेनमार्क इस मुद्दे पर कुछ कर नहीं सकता। उनका कहना था कि ग्रीनलैंड में सुरक्षा के लिए केवल दो डॉगस्लेड उपलब्ध हैं, जिनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत में 6 करोड़ रुपये की कीमत का कोबरा का 6.5 एमएल ज़हर बरामद,सात आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद के एक सोनी से लाया गया था, रेव पार्टियों में इस ज़हर से नशा किया जाता है

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत एस.ओ.जी. पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात में पहली बार करीब 5.85 करोड़ रुपये की कीमत का कोबरा सांप का ज़हर पकड़ा गया है। इस ऑपरेशन में लसकाणा पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो करोड़ों रुपये के इस ज़हर को बेचने की फिराक में थे। आरोपियों के पास से करीब 6.5 एमएल कोबरा वेनम ज़ब्त किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 5,85,00,000 रुपये बताई जा रही है।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह ज़हर अहमदाबाद के एक सोनी से लाया गया था और आरोपी इसे सूरत में बेचने की तैयारी कर रहे थे। गौरतलब है कि सांप के ज़हर का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर सहित कई दवाइयों के निर्माण में होता है, लेकिन हाल के दिनों में रेव पार्टियों में नशे के लिए इसके अवैध उपयोग के मामले भी बढ़े हैं। इसी वजह से पुलिस अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए गहन जांच कर रही है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह ज़हर अहमदाबाद के एक सोनी से लाया गया था। आरोपी लसकाणा और सरथाणा इलाकों में इस कीमती ज़हर की बिक्री के लिए नेटवर्क फैला रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण उनकी योजना नाकाम हो गई।

ज़हर सप्लाई करने वाले अहमदाबाद के सोनी की तलाश

इस कार्रवाई के बाद सूरत पुलिस अब ज़हर की सप्लाई चेन की

गहराई से जांच कर रही है। खास तौर पर उस अहमदाबाद के सोनी की तलाश की जा रही है, जिसने यह ज़हर उपलब्ध कराया था। गुजरात में इस तरह के मामले के खुलासे से वन्यजीव सुरक्षा और अवैध ड्रग नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

काले कारोबार की कड़ियां अहमदाबाद से सूरत तक

सूरत एसओजी टीम ने सूचना के आधार पर छापा मारकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति एमएल 90 लाख रुपये की कीमत वाले 6.5 एमएल ज़हर को जब्त किया।

वडोदरा के चार और सूरत के तीन लोग मिलकर यह खतरनाक खेल खेल रहे थे। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग भी जांच में शामिल हो गया है और लैब रिपोर्ट आने के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सात आरोपियों में 5 वडोदरा के और 2 सूरत के गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों में सूरत के 2 और वडोदरा के 5 लोग शामिल हैं। इनमें
67 वर्षीय मनसुख घीनैया,
60 वर्षीय चीमन भुवा,
41 वर्षीय समीर पंचाल,
74 वर्षीय प्रवीण शाह,
50 वर्षीय केतन शाह,
54 वर्षीय मकरंद कुलकर्णी और
40 वर्षीय प्रशांत शाह शामिल हैं।

यह करोड़ों रुपये का काला कारोबार अहमदाबाद से सूरत तक जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद के आरटीओ सर्कल के पास रहने वाले मुख्य सूत्रधार घनश्याम सोनी ने वडोदरा के प्रशांत और मकरंद को यह ज़हर बिक्री के लिए दिया था।

ज़हर का सौदा 9 करोड़ रुपये में फाइनल हुआ था। यह गिरोह सूरत में मैरेज ब्यूरो चलाने वाले मनसुख घीनैया के संपर्क में था, जहां यह सौदा 9 करोड़ रुपये में तय हुआ था। इतनी बड़ी रकम के सौदे में सभी के कमीशन तय थे, लेकिन सौदा पूरा होने से पहले ही पुलिस ने फिल्मी अंदाज़ में छापा मारकर, वडोदरा के एक एडवोकेट सहित सातों आरोपियों की साजिश नाकाम कर दी।

ज़हर कहां से लाया गया?

कोबरा वेनम का उपयोग सिर्फ जीवनरक्षक दवाइयों या एंटी-वेनम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आशंका है कि हाई-प्रोफाइल रेव पार्टियों में नशे के लिए 'स्नेक बाइट' के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती घनश्याम सोनी को पकड़ना है, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि इतना महंगा ज़हर कहां से लाया गया और इसके पीछे किस बड़े गिरोह का हाथ है। फिलहाल इन सातों आरोपियों की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।

'रेव पार्टियों में कुछ लोग सांप के ज़हर से नशा करते हैं'एसओजी के डीसीपी राजदीप सिंह नकुम ने बताया कि यह वेनम प्रतिबंधित है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमत प्रति एमएल 90 लाख रुपये मानी जाती है।

इसका उपयोग अलग-अलग दवाइयों में होता है—जैसे बीपी की दवाएं, खून के थक्के जमने से रोकने की दवाएं, हार्ट अटैक से बचाव आदि।

इसके अलावा सांप के काटने के इलाज में एंटी-वेनम के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही, कुछ बड़ी रेव पार्टियों में 'स्नेक बाइट' या सांप के ज़हर से नशा करने के लिए भी इसका उपयोग किए जाने की बातें सामने आई हैं।

रिसकाइड डॉमिनेटर्स ने जीती अग्रवाल प्रीमियम लीग-17

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विकास ट्रस्ट युवा शाखा द्वारा आयोजित अग्रवाल प्रीमियम लीग का फाइनल मैच रविवार को अलथान स्थित बीजे पटेल क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। लीग में रिसकाइड डॉमिनेटर्स विजेता एवं वेदांशी रॉयल्स उपविजेता बनी। अंडर-16 ग्रुप में थ्रीसीएस एंड को. रॉयल्स विजेता बनी। तीन दिवसीय लीग का आयोजन स्वदेशी थीम पर रखा गया था। लीग के दौरान ट्रस्ट द्वारा कार्निवल, भिवानी की सब्जी आदि का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर अग्रवाल विकास ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अलावा युवा एवं महिला शाखा के अनेकों सदस्य उपस्थित रहें।

नित्या महेश्वरी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अंतरराष्ट्रीय रैंक प्रथम प्राप्त की

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विद्या विहार स्कूल की छात्रा नित्या महेश्वरी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अंतरराष्ट्रीय रैंक प्रथम प्राप्त किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया की यह उपलब्धि हासिल कर नित्या ने विद्यालय और ट्रस्ट नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है।

ज्ञात रहे की इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड विश्व स्तर पर आयोजित एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, जो विद्यार्थियों की तार्किक सोच, गणितीय समझ और समस्या-समाधान क्षमता का आकलन करती है। इस शानदार उपलब्धि के लिए नित्या, उनके माता-पिता एवं शिक्षकों को ट्रस्ट द्वारा हार्दिक बधाई दी गई।

स्कूल से घर लौट रही कक्षा 6 की छात्रा से छेड़छाड

विकृत मानसिकता वाले दो दोस्तों की करतूत CCTV में कैद पुलिस ने आरोपियों को खोजकर कानून का सबक सिखाया

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के अमरोली क्षेत्र में कक्षा 6 में पढ़ने वाली 11 वर्षीय छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान दो युवकों ने उसका पीछा किया और सार्वजनिक स्थान पर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए अश्लील हरकत की। अमरोली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें घटनास्थल पर ले गई और कानून का पाठ पढ़ाते हुए उनसे माफी मंगवाई।

मिली जानकारी के अनुसार, अमरोली क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की 11 वर्षीय बेटी पिछले शनिवार को स्कूल गई थी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद वह अकेली घर लौट रही थी, तभी दो अज्ञात युवक उसके पीछे पड़ गए। पहले उन्होंने उसका नाम पूछा। किशोरी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, 'मेरा नाम जानकर क्या करोगे?' और अपनी चाल तेज कर दी।

एक युवक ने हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा लेकिन विकृत मानसिकता वाले युवकों ने पीछा नहीं छोड़ा। वे यह पूछने लगे कि वह किस स्कूल में पढ़ती है और उसे परेशान करने लगे। इससे पहले कि किशोरी कुछ समझ पाती, उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और छेड़छाड़ की। घबराई हुई किशोरी ने सूझबूझ दिखाते हुए विरोध किया और वहां से भागकर सीधे घर पहुंच गई।

CCTV में टपोरियों की शर्मनाक हरकत कैद घर पहुंचने पर बच्ची बेहद घबराई हुई और रो रही थी। मां ने पूछताछ की तो पूरी घटना सामने आई। परिवार ने तुरंत अमरोली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें आरोपियों की शर्मनाक हरकतें कैद मिलीं।

दोनों आरोपी स्थानीय तबेले में साथ काम करते हैं फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान राजकुमार

जल्लू यादव (उम्र 20 वर्ष, निवासी मणि पुरुषोत्तम नगर, छापराभाठा, मूल निवासी बनारस, यूपी) और मुकेश रत्नाभाई मीर (उम्र 20 वर्ष, निवासी वाळीनाथ सोसायटी, छापराभाठा, मूल निवासी ढोलका) के रूप में की। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी स्थानीय तबेले में साथ काम करते हैं।

हजीरा के पुराने गांव में पंजाबी युवक की हत्या

गला और सिर पर धारदार हथियार से वार रूम पार्टनरों द्वारा हत्या की आशंका

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर के हजीरा क्षेत्र स्थित पुराने गांव के डेरी फलिया इलाके में एक हत्या की घटना सामने आई है। यहां किराए पर रहने वाले एक युवक की हत्या के पीछे उसके ही दो रूम पार्टनरों का हाथ होने की आशंका पुलिस जता रही है। फिलहाल मकान मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस को प्राथमिक तौर पर यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है।

घटना के विवरण के अनुसार, हजीरा के पुराने गांव में मेहुलकुमार छबीलभाई पटेल के मकान में पंजाब के मूल निवासी तीन युवक किराए पर रहते थे। मृतक शेरासिंह हरभजन सिंह अपने दो साथियों सरबजीत सिंह और अमरीक सिंह के साथ पिछले कुछ समय से यहां रह रहा था। तीनों रोज़गार के लिए पंजाब से सूरत आए थे और किराए के कमरे में रहकर अपना गुजर-बसर कर रहे थे।

दोनों ने मन में रंजिश पाल रखी थी मिली जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले मृतक शेरासिंह का उसके दोनों रूम पार्टनरों सरबजीत सिंह और अमरीक सिंह के साथ किसी बात को लेकर तीखी बहस और झगड़ा हुआ था। उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन आशंका है कि दोनों आरोपियों ने मन में रंजिश पाल ली थी और शेरासिंह को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

गला और सिर पर धारदार हथियार से कई वार 17 जनवरी 2026 को शाम करीब 5 बजे, जब मकान मालिक मेहुलकुमार को जानकारी मिली कि शेरासिंह अपने कमरे में खून से लथपथ पड़ा है, तो वे स्तब्ध रह गए। जांच में पता चला कि शेरासिंह के गले और सिर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

अग्रवाल प्रीमियम लीग-17 की हुई रंगारंग शुरुआत

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत,अग्रवाल विकास ट्रस्ट द्वारा अग्रवाल प्रीमियर लीग-17 की रंगारंग शुरुआत शुक्रवार को अलथान स्थित बी.जे. पटेल क्रिकेट ग्राउंड पर सुबह साढ़े सात बजे किया गया। इस अवसर पर सभी टीमों के खिलाड़ी, खेल प्रेमी एवं समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ट्रस्ट द्वारा उद्घाटन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

लीग का आयोजन 'स्वदेशी' थीम पर आधारित किया गया है। जिसका उद्देश्य भारतीय ब्रांड्स एवं उत्पादों को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में समाज को जागरूक करना है। इस अवसर पर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, उनके महत्व एवं भारतीय उद्योगों को समर्थन देने के संदेश दिए गए।

डे-नाइट प्रारूप में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 12 सीनियर टीमें एवं 3 अंडर-16 टीमें भाग ले रही हैं। सभी मैच लीग टेनिस बॉल से खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।

टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रमोद पोद्दार, संजय सरावगी, अनिल शेरोवाला, राजीव गुप्ता, राहुल अग्रवाल, शशिभूषण जैन, रमेश अग्रवाल, प्रमोद कंसल, दिनेश अग्रवाल सहित अनेकों सदस्य उपस्थित रहें।

800 करोड़ के 'एन मार्ट' घोटाले के मास्टरमाइंड 11 साल बाद गिरफ्तार

देश के 6 राज्यों में हजारों निवेशकों को लगाया चूना एक दशक से सूरत क्राइम ब्रांच को दे रहे थे चकमा

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले एक दशक से फरार चल रहे दो बेहद अहम वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

डुप्लिकेट दस्तावेजों के आधार पर 'एन मार्ट' (N Mart) मॉल शुरू कर देशभर में 800 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले गोपाल शेखावत और मोहम्मद सलीमखान को पुलिस ने दबोच लिया है। दोनों आरोपी पिछले 11 वर्षों से पुलिस से बचते फिर रहे थे।

आरोपियों ने अडाजण इलाके में फर्जी दस्तावेज तैयार कर एन मार्ट, न्यू लुक मल्टी ट्रेड और न्यू लुक रिटेल्स जैसी कंपनियां खड़ी कीं।

मॉल की फ्रेंचाइज़ी देने के नाम पर गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के 6 राज्यों के हजारों लोगों को करोड़ों रुपये के निवेश का लालच दिया।

आरोपियों के खिलाफ गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कुल 54 मामले दर्ज हैं।